

भगवान जगन्नाथ के तीन रथों के निर्माण कार्य का शुभारंभ, ओडिशा के जंगलों से लाई गई लकड़ियां

नई दिल्ली (एजेंसी)। त्र्यागराज नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के तीन रथों के निर्माण कार्य का शुभारंभ पूरे रीति-रिवाज के साथ शुरू हुआ। यह समारोह पुरी के मुख्य जगन्नाथ धाम में अपनाई जाने वाली परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार वैदिक मंत्रों के उच्चारण और जगन्नाथ स्वामी की जय के जयघोष के बीच संपन्न हुआ। पवित्र लकड़ियों की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाने वाले अनीकरीत साहू भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने मुख्य कर्ता के रूप में पूजा-अर्चना संपन्न की। इस अवसर पर कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, त्र्यागराज के विधायक नीरज बसोया और नई दिल्ली की सांसद बासुरी स्वराज भी उपस्थित रही। इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समारोह में शामिल हुए। त्र्यागराज जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन ने बताया कि ओडिशा के बाहर पहली बार, 16 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव के दिन जगन्नाथ मार्ग पर तीन मूर्तियों के तीन रथ खींचे जाएंगे। प्रबंधन के अधिकारियों ने बताया कि इन रथों के लिए ओडिशा के ही कुछ श्रद्धालुओं ने ओडिशा के जंगलों से पवित्र लकड़ियों को एकत्रित कर, इलदेहाड़ (ओडिशा) में आयोजित एक विशेष समारोह के माध्यम से उन्हें यहाँ तक पहुंचाने की व्यवस्था की। पूजा समारोह में ओडिशा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद (राज्यसभा) मनमोहन सामल उपस्थित रहे।

5 लाख महिलाओं के हाथ में आया 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड'

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में बसों के भीतर महिलाओं के मुफ्त साफर के लिए अब 5.30 लाख महिलाओं ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनाया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा कि यह संख्या न केवल इस योजना की सफलता को प्रमाणित करती है, बल्कि दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर महिलाओं के बढ़ते भरोसे और सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली की हर बेटा और महिला की सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध है। 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' केवल मुफ्त यात्रा का पास नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को एक डिजिटल पहचान और सम्मानजनक साफर का अनुभव देने वाला सशक्त माध्यम है। सार्वजनिक परिवहन जब सुलभ और सुरक्षित होता है तो महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और प्रगति के अवसर अपने आप ही बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 'टैप-एंड-गो' तकनीक पर आधारित एनसीएमसी कार्ड है। अब महिलाओं को कागजी टिकट लेने की जरूरत नहीं है। केवल इंटैपम मशीन पर कार्ड टैप करें और अपनी सीट लें। इस कार्ड की मदद से महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को बस में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिल रही है। यही स्मार्ट कार्ड भूगोल दंकर मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह योजना 5 वर्ष से अधिक उम्र की दिल्ली की सभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कार्ड से हर महिला को महीने में 1, 200 से 2,400 रुपये तक की बचत हो रही है। उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में इस योजना का विस्तार और अधिक प्रभावी ढंग से होगा।

पुराने चेक की वैधता खत्म होने पर नहीं बनता अपराध : कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। द्वारका जिला अदालत ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि चेक अपनी वैधता अधि समाप्त होने के बाद बैंक में पेश किया जाता है तो यह नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स (एनआई) अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नितेश गोयल की अदालत ने 27.10 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी गुरमीत को बरी कर दिया है। यह मामला पारिवारिक रिश्तों से जुड़ा था, जहां शिकायतकर्ता सुषमा दलाल ने अपने करीबी रिश्तेदार को वर्षों पहले बड़ी रकम उधार देने का दावा किया। शिकायत के अनुसार, आरोपी गुरमीत ने वर्ष 2016 में मकान निर्माण और निजी जरूरतों के लिए करीब 70 लाख रुपये उधार लिए थे, जिसमें से कुछ रकम लौटाने के बाद शेष भुगतान के लिए वर्ष 2023 में 27.10 लाख रुपये का चेक जारी किया गया। जब यह चेक अक्टूबर 2023 में बैंक में लगाया गया तो वह विलयिंग मोड उपलब्ध नहीं होने के कारण लौट आया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजकर मामला अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संबंधित बैंक (ओरिएंटल बैंक ऑफ़ॉर्मर्स) का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुका था और पुराने चेकबुक की वैधता 30 सितंबर 2021 तक ही थी। ऐसे में 30 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत किया गया चेक पहले ही अपनी वैधता खो चुका था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध तभी बनता है जब चेक अपनी वैध अवधि के भीतर पेश किया जाए और अन्य सभी शर्तें भी पूरी हों। चूंकि इस मामले में चेक ही समयसीमा के बाद लगाया गया, इसलिए कानून की मूल शर्त पूरी नहीं हुई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही आरोपी ने चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार किए हों और कानून में देनदारी का अनुमान भी लगाया जाता हो, लेकिन यदि चेक वैध ही नहीं है तो आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। इस तरह अदालत ने तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण आधार पर आरोपी को बरी करते हुए यह संदेश दिया कि चेक बाउंस मामलों में समयसीमा और वैधता की शर्तें बेहद अहम हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

वॉयस ऑफ ह्यूमन फाउंडेशन का सामूहिक विवाह, 11 जोड़े बने जीवनसाथी



नई दिल्ली (एजेंसी)। वॉयस ऑफ ह्यूमन फाउंडेशन द्वारा पाँचवाँ सामूहिक विवाह समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें 11 जोड़ों ने एक साथ वैवाहिक बंधन में बंधकर नए जीवन की शुरुआत की। समारोह के दौरान संस्था ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक परेल्स सामान और उपहार भेंट किए। यह पहला आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समानापूर्वक विवाह का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास मानी जा रही है। कार्यक्रम में स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और समाजसेवियों ने भाग लेकर संस्था के कार्यों की प्रशंसा की। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सहयोग और संवेदनशीलता की भावना को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर संस्था की वंदना ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अभावग्रस्त कन्याओं का विवाह करना अत्यंत पुण्य का कार्य है और इसमें सहयोग करने वाले सभी लोग इसके भागीदार हैं। संस्था ने भविष्य में भी इस प्रकार के सामाजिक कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया।

दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल, पुलिस में हजारों पद खाली : डॉ. नरेश कुमार

नई दिल्ली (एजेंसी)। डॉ. नरेश कुमार ने राजधानी की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपते हुए गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई संवेदनशील मामलों में पुलिस की निष्क्रियता से जनता के बीच असुरक्षा का माहौल बन रहा है। उन्होंने गार्मी कॉलेज में अत्याचारा, सीआर पार्क में दोहरे हत्याकांड और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भावनों के बाहर हुए हमामे जैसे घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मामलों में पुलिस की चुप्पी चिंताजनक है। उनके अनुसार, बढ़ते अपराधों के बावजूद समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दिल्ली पुलिस में स्वीकृत 97,331 पदों में से 14, 140 पद खाली हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने और बढ़ती आबादी के अनुरूप नए पुलिस थानों की स्थापना की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को संविधान और कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक दबाव में। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गार्मी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव के दौरान जनरल प्रवेश की घटनाओं और अन्य मामलों में भी पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की।

एक साल में बदली एमसीडी की तस्वीर, आगे 'मॉडल शहर' का लक्ष्य: सत्या शर्मा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने दावा किया है कि पिछले एक वर्ष में एमसीडी में हुए बदलाव केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह एक व्यापक परिवर्तन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि निगम ने लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर ठोस कार्रवाई करते हुए व्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ-साथ विकास की नई दिशा भी तय की है।

सत्या शर्मा के अनुसार यह परिवर्तन नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन, अमित शाह के मार्गदर्शन और रेखा गुप्ता के नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन नीतियों दिशाओं ने निगम को नई ऊर्जा और स्पष्ट लक्ष्य प्रदान किया है।

विधायी मसौदा-निर्माण लोकतांत्रिक शासन का मूल है : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। विधायी मसौदा-निर्माण लोकतांत्रिक शासन का मूल है किसी कानून की सटीकता ही तय करती है कि वह अधिकारों की रक्षा कितनी प्रभावी ढंग से करता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है और आम नागरिकों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। उक्त बातें दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधान सभा के दौर पर आए 18 देशों के 43 प्रतिनिधियों के दल को संबोधित करते हुए कही। ये प्रतिनिधि बांग्लादेश, भूटान, ओमान, केन्या, श्रीलंका, फिलीपींस और तंजानिया सहित विभिन्न देशों से आए थे और लोकसभा सचिवालय के संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान



(प्राइड) द्वारा आयोजित 37वें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा परिसर को एक विरासत स्थल के रूप में

वाली परियोजनाओं को तेज किया गया है, जिससे राजधानी को कचरा मुक्त शहर बनाने की दिशा में तेजी आई है।

कर्मचारियों के हितों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नियमितकरण, समय पर वेतन और पेंशन तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। वहीं वित्तीय मोर्चे पर निगम ने रिकॉर्ड स्तर पर संपत्ति कर संग्रह करते हुए पहली बार लाभ वाला बजट प्रस्तुत किया है, जो वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का संकेत है।

भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए सत्या शर्मा ने कहा कि अब लक्ष्य केवल सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली को एक आदर्श शहरी ढांचे में विकसित करना है। एक सड़क-

एक दिन+ योजना के तहत रोजाना एक सड़क को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही तीनों लैंडफिल स्थलों को समाप्त कर उन्हें हरित क्षेत्र और सार्वजनिक उपयोग के स्थानों में परिवर्तित करने की योजना है।

उन्होंने यह भी बताया कि हर वार्ड में स्वास्थ्य और सामुदायिक सुविधाओं का विस्तार, डिजिटल सेवाओं को सरल बनाना, प्रदूषण नियंत्रण के लिए निरंतर निगरानी प्रणाली स्थापित करना तथा विद्युत वाहन चार्जिंग और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके साथ ही बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान और नागरिक सहभागिता को बढ़ाकर राजधानी को हरित और टिकाऊ शहर बनाने पर विशेष ध्यान



दिया जाएगा।

सत्या शर्मा ने कहा कि एक वर्ष में परिवर्तन की मजबूत नींव रखी जा चुकी है और आने वाले समय में यह बदलाव दिल्ली की पहचान बनेगा।

एबीवीपी ने 12 मांगों को लेकर डीयू में निकाला 'छात्र अधिकार मार्च'



नई दिल्ली (एजेंसी)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की मूलभूत समस्याओं और अधिकारों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में विशाल 'छात्र अधिकार मार्च' का आयोजन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष 12 प्रमुख मांगों का एक मांगपत्र रखा है, जो छात्रों के शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे से जुड़े सुधारों पर केंद्रित है। परिषद की मुख्य मांगों में विश्वविद्यालय को 'पोर्टेबल' मुक्त बनाना, अनिर्वाय फ़रार सेप्टी ऑडिट सुनिश्चित करना और 30 अप्रैल 2026 तक परीक्षा फॉर्म को लेट फ़ैस से छूट दिलाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अभावित पांच वर्षीय लॉ बीए एलएलबी (ऑनर्स) की शुल्क को घटाने, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन, नए हॉस्टलों का निर्माण और एक 'सेंट्रलाइज्ड एलमेंट सेल' की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण मांग उठाई। सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देते हुए एबीवीपी ने थर्ड जेंडर छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे को विद्यांग सुगम्य बनाने पर भी विशेष जोर दिया है। एबीवीपी ने 'एक कोर्स, एक फ़ैस' और अकादमिक काउंसिल में छात्रों के प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए कॉलेज कैंटीन में स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने की भी पुरजोर अपील की है। एबीवीपी दिल्ली के प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने कहा कि यह 'छात्र अधिकार मार्च' दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के विरुद्ध छात्रों का एक निर्णायक शखनाह है। एबीवीपी ने जिन 12 मांगों को उठाया है, वे छात्रों के भविष्य और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। आज हमारे आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर यह मांग की कि यदि प्रशासन इन 12 मांगों पर तत्काल सकारात्मक कदम नहीं उठाता है तो एबीवीपी छात्र हितों की रक्षा के लिए और भी उग्र आंदोलन करेगी।

उन्होंने विश्वास जताया कि एमसीडी विकसित, स्वच्छ और आधुनिक राजधानी के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेगी।

दक्षिणी जोन में कार्यों की समीक्षा, समयसीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। संजीव खिरवार ने दक्षिणी जोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण का उद्देश्य मुख्यमंत्री विकास निधि के अंतर्गत प्रगति, डीसिल्टिंग कार्यों और स्वच्छता व्यवस्था का आकलन करना रहा।

निरीक्षण के दौरान ग्रीन पार्क और आसपास के इलाकों में सड़क परियोजनाओं का जायजा लिया गया। इस अवसर पर दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयुक्त ने कार्यों की गुणवत्ता पर संतोष जताते हुए शेष परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को बेहतर आवाजही सुविधा मिल सके।

विकसित किया जा रहा है, जहां एक सग्रहालय बनाया जा रहा है जो विधानसभा की यात्रा को दर्शाएगा। इसके अलावा, इसके इतिहास को



दक्षिणी जोन में स्वच्छता के मानकों में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला आरक्षण पर सियासत तेज, भाजपा पर 'छिपे एजेंडे' का आरोप: शोभा ओझा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व महिला अध्यक्ष शोभा ओझा ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संसद में संशोधन विधेयक के जरिए अपने 'छिपे हुए एजेंडे' को लागू करना चाहती थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने विफल कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई।

राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शोभा ओझा ने कहा कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कांग्रेस के समर्थन से दोनों सदन में मंजूरी मिली थी, जिसमें जनगणना के आधार पर सीटों का परिसीमन कर महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रस्ताव 2011 की जनगणना के



आधार पर लागू करने की कोशिश की गई, जो वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है और लोकतंत्र तथा संविधान की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया है। ओझा के अनुसार भाजपा की विचारधारा महिलाओं के हितों के विपरीत रही है और इतिहास में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली

पर परिसीमन कर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू किया जाए, न कि इसे आगे टालकर 2034 तक ले जाया जाए।

वहीं पुष्पा सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण की बुनियाद कांग्रेस ने रखी थी और पंचायती राज तथा नगर निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के प्रयासों से ही महिलाओं को शासन के विभिन्न स्तरों पर अवसर मिला है और पार्टी आज भी इस दिशा में संघर्ष कर रही है।

कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि मौजूदा लोकसभा सीटों पर एक तिहाई महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, ओबीसी महिलाओं के लिए उप-कोटा सुनिश्चित किया जाए और महिला सुरक्षा के मामलों में जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक महिलाओं को उच्च अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।

नरेंद्र नाथ ने कहा कि संसद में विधेयक को बहुमत में मिलाना सरकार की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने मांग की कि 2021 की जनगणना के आधार

धीरे धीरे खत्म होने लगा सार्वजनिक पुस्तकालय का चलन: जनरल वीके सिंह

-बदल रहा है लाइब्रेरी का स्वरूप, लेकिन खत्म नहीं होगी पुस्तकों की आवश्यकता : प्रो. योगेश सिंह

-डीयू के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का 80 वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग का 80 वां स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर जनरल वीके सिंह ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के समाप्त होने पर चिंता व्यक्त की। डीयू में अतिरिक्त एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहां वो चीज प्राप्त करते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकती। अगर आप

यूरोप में जाएं तो वहां सार्वजनिक पुस्तकालयों पर सबसे ज्यादा जोर देखने को मिलता है। हमारे यहां भी पहले सार्वजनिक पुस्तकालय थे, धीरे धीरे उनका चलन खत्म होने लगा, कुछ जगह पर अभी भी हैं, लेकिन शायद उनकी देखरेख उतनी नहीं है, जितना कि उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। अब समय है कि हम उन्हें और अच्छा बना सकें, ताकि सब लोगों को उनका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि विश्वविद्यालयों से ही देश के उच्चतम लोग निकल पाते हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय था जब लाइब्रेरी का अपना महत्व था। आप किसी भी संस्था का आकलन करना चाहते थे तो, उसकी लाइब्रेरी से उसका आकलन होता था। अब लाइब्रेरी का स्वरूप बदल गया है। लाइब्रेरी और इनफार्मेशन साइंस का अपना एक अलग महत्व है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की जरूरत



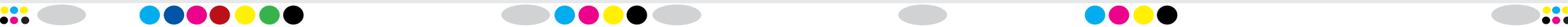
होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीयू कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि तकनीक के कारण आज लाइब्रेरी का स्वरूप बदल रहा है, लेकिन पुस्तकों की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ने की आदत बनाए रखना जरूरी है। पुस्तकों का तरीका बदल सकता है, उनके प्रकाशन का माध्यम बदल सकता है, लेकिन उनकी उपयोगिता कम नहीं हो सकती। प्रो. योगेश सिंह ने कहा कि प्राचीन काल में हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय विश्व प्रसिद्ध था। दुनिया के अनेकों देशों से स्कॉलर वहां पढ़ने आते थे।

कुलपति ने कहा कि भारत में बीसवीं शताब्दी के आरंभ में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना करने की शुरुआत का श्रेय बख्शीव के महाराजा सियाजीराव को जाता है। उन्होंने



अमरीका के विलियम एलनसन बोर्डेन अपनी रियासत में पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए आमंत्रित किया। बीएचयू (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) की मुख्य

लाइब्रेरी का नाम उन्हें के नाम पर सयाजीराव अपनी रियासत में पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए आमंत्रित किया। बीएचयू (बनारस हिंदू विश्वविद्यालय) की मुख्य



डीएम की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई, अधिकारियों को दिए त्वरित कार्यवाही के आदेश

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। डीएम रविन्द्र कुमार मोंड ने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान राजस्व विभाग, जीडीए, नगर निगम, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से सम्बंधित प्रार्थना व शिकायतों का निराकरण किया गया।



उनके साथ जूम पर लाइव रहेंगे। जनसुनवाई के दौरान कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया एवं जूम के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर उन्हें शिकायतों से अवगत कराते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के आदेश दिए। डीएम ने जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांगजन महिला, जिसका नाम दीनमनी शर्मा को

दिव्यांगजन कल्याण विभाग से श्रवण यंत्र एवं मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल और दूसरे दिव्यांगजन दीपक को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। जनसुनवाई के दौरान एडीएम सिटी विकास कश्यप, एडीएम जे. अंजुम बी, जिला दिव्यांगजन सहायक अधिकारी अंशुल चौहान सहित अन्य अधिकारियों को उपस्थित रहे।

नगर निगम मुख्यालय पर हुआ संभव के तहत जनसुनवाई का आयोजन

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। नगर निगम मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को संभव के तहत जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। आज की गई जनसुनवाई के दौरान 21 समस्याएं नगर निगम अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं। समस्याओं में 13 निर्माण विभाग, 4 उद्यान विभाग, 2 टैक्स और 2 एंक्रोचमेंट से संबंधित प्राप्त हुईं। प्राप्त सभी समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश सभी विभाग अध्यक्षों को दिए गए। अंतर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव ने बताया कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक मंगलवार को संभव के तहत जनसुनवाई का आयोजन नगर निगम मुख्यालय पर किया जाता है।



जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जाता है। समस्या का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग अध्यक्ष को आदेशित किया जाता है। उन्होंने बताया कि समस्या का निस्तारण करने के बाद फरियादी से समस्या से संबंधित फीडबैक भी लिया जाता है। स्थलीय समस्याओं का निस्तारण करने के लिए नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचकर समस्या का निस्तारण कर रहे हैं। जनसुनवाई के दौरान उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संतोष कुमार राव, प्रभारी संपत्ति पल्लवी सिंह व अन्य मौजूद रहे।

सरस्वती मेडिकल कॉलेज में लाइव मॉक ड्रिल, अग्नि सुरक्षा को लेकर किया जागरूक

हापड़ (शिखर समाचार)। अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्यापक अग्नि सुरक्षा मॉक ड्रिल एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्टाफ, विद्यार्थियों और आगंतुकों को अग्नि सुरक्षा, संभावित खतरों की पहचान तथा आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान विस्तृत प्रदर्शन और संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अग्निशमन उपकरणों के सही उपयोग और आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई। मुख्य आकर्षण लाइव डेमो रहा, जिसमें अग्निशमक यंत्रों के उपयोग की पास तकनीक खींचें, निशाना लगाएं, दबाएं और झाड़ू की तरह चलाएं को व्यावहारिक रूप से समझाया गया। साथ ही रेस प्रोटोकॉल बचाव, सतर्क करना, नियंत्रित करना और निकासी के तहत आपातकालीन स्थिति में उठाए जाने वाले जरूरी कदमों की जानकारी दी



गई। अग्नि सुरक्षा टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमक यंत्र, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, श्वसन यंत्र सहित अन्य आपातकालीन उपकरणों का प्रदर्शन किया। प्रभागियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें वास्तविक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों की निगरानी में आउटडोर मॉक ड्रिल भी आयोजित की गई, जिसमें आपात स्थिति का वास्तविक अनुकरण करते हुए निकासी प्रक्रिया, समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया का अभ्यास कराया गया। इस अभ्यास ने प्रतिभागियों को टीमवर्क, सतर्कता और समय पर

क्रॉसिंग गोल चक्कर पर मार्केट में लगी आग, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के गोल चक्कर पर मंगलवार की सुबह मार्केट में अचानक आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और भगदड़ का माहौल बन गया। आग का धुआं काफी दूर तक दिखाई देने लगा और धुएं को देखकर लोगों का जमावड़ा मौके पर लग गया। आग की सूचना दमकल विभाग की टीम को दी गई। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाना शुरू किया। इसी दौरान दमकल विभाग को सूचना मिली की अजनारा जैनएक्स सोसायटी के 20 वे तल पर एक फ्लैट में आग लग गई है। आग की गंभीरता को देखते हुए दूसरे जनपद से भी फायर टैंकर मौके पर मंगाए गए। गौतम बुध नगर के चीफ फायर ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे। गाजियाबाद व गौतम बुध नगर की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मार्केट और फ्लैट में लगी आग पर काबू पाया। गनीमत रही की आग लगने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई और समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया, वरना क्रॉसिंग रिपब्लिक का सीएनजी पंप और अन्य सोसायटी भी आग की चपेट में आ सकती थी। चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि सुबह लगभग 11 बजे फायर स्टेशन कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि क्रॉसिंग-रिपब्लिक गोल चक्कर के पास दुकानों में आग लग गई है। सूचना पर तत्काल फायर टैंकर घटनास्थल के लिए रवाना किए गए। घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि आग विकराल रूप से जल रही थी और मौके की नजदीक को देखते हुए अन्य फायर स्टेशन वैशाली, कोतवाली, साहिबाबाद व जनपद गौतमबुधनगर से फायर टैंकर की घटनास्थल

पर बुलाये गए। फायर सर्विस यूनिट ने तत्काल दो लाइन बनाकर दुकानों की आग को बुझाना आरंभ किया। दुकानों की आग को बुझाया जा रहा था। इसी बीच पास स्थित अजनारा जैनएक्स सोसायटी के 20 वे तल पर अरुणोदय वर्मा के फ्लैट नंबर एम-2006 में आग लग गई। तत्काल फायर सर्विस यूनिट सोसायटी पर पहुंची और अथक परिश्रम कर फ्लैट की आग को बुझकर शांत किया गया। फ्लैट में एक कमरे में आग लगी थी, जिसमें तीन एसी, दो मेज, एक एलईडी टीवी व कमरे की दीवार क्षतिग्रस्त हुई। उन्होंने बताया कि लगभग-20 दुकानों में आग लगी थी, जो अस्थायी रूप से तीन शैड से निर्मित थी। दुकानों की आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है और आग से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर यूनिट ने त्वरित कार्यवाही करते हुए पास स्थित अन्य कई दुकानों, मॉडल वाइन शॉप और आईजीएल सीएनजी पंप को सुरक्षित बना लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए 6 फायर टैंकर, 5 वाटर बाउजर व एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया गया।



पुलिस ने जब टैपों की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में नीले ड्रम मौजूद थे। पुलिस ने जब ड्रम को चेक किया तो उसमें पनीर मौजूद था। पुलिस ने तत्काल दो लोगों को हिरासत में लेते हुए खाद्य विभाग को सूचना दी। खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पनीर निकला। टीम ने पनीर का जमावड़ा भी किया तो पनीर 900 किलो था। खाद्य विभाग की टीम में सिंथेटिक पनीर को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। खाद्य अधिकारी अशुतोष राय ने बताया कि थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने सूचना दी थी कि वेकिंग के दौरान उन्होंने मथुरा से दिल्ली जा रहे एक टैपों को रोका था। टैपों में बड़ी मात्रा में पनीर मौजूद है। सूचना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल मौके पर टीम रवाना की गई। पनीर का सैपल चेक किया गया तो वह सिंथेटिक पनीर पाया गया। सिंथेटिक पनीर को खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि वह यह सिंथेटिक पनीर कहा से लाए थे और दिल्ली में किसको देने जा रहे थे।

शालीमार गार्डन पुलिस ने पकड़ा 900 किलो सिंथेटिक पनीर, खाद्य विभाग ने किया नष्ट

गाजियाबाद (शिखर समाचार)। थाना शालीमार गार्डन पुलिस क्षेत्र में वेकिंग कर रही थी। वेकिंग के दौरान पुलिस को एक टैपों आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने जब टैपों की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में नीले ड्रम मौजूद थे। पुलिस ने जब ड्रम को चेक किया तो उसमें पनीर मौजूद था। पुलिस ने तत्काल दो लोगों को हिरासत में लेते हुए खाद्य विभाग को सूचना दी। खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पनीर निकला। टीम ने पनीर का जमावड़ा भी किया तो पनीर 900 किलो था। खाद्य विभाग की टीम में सिंथेटिक पनीर को नष्ट कर दिया है। इसके अलावा हिरासत में लिए गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है। खाद्य अधिकारी अशुतोष राय ने बताया कि थाना शालीमार गार्डन पुलिस ने सूचना दी थी कि वेकिंग के दौरान उन्होंने मथुरा से दिल्ली जा रहे एक टैपों को रोका था। टैपों में बड़ी मात्रा में पनीर मौजूद है। सूचना की गंभीरता को समझते हुए तत्काल मौके पर टीम रवाना की गई। पनीर का सैपल चेक किया गया तो वह सिंथेटिक पनीर पाया गया। सिंथेटिक पनीर को खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए दोनों अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि वह यह सिंथेटिक पनीर कहा से लाए थे और दिल्ली में किसको देने जा रहे थे।

नगीना में एम्स की मांग को लेकर शुरू हुआ पोस्टकार्ड अभियान



नगीना/बिजनौर (शिखर समाचार)। नगीना में एम्स बनवाने की मांग को लेकर नागरिकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित पोस्टकार्ड अभियान शुरू किया है। लोगों का मानना है कि इस माध्यम से उनकी मांग सही सरकार तक पहुंचेगी और क्षेत्र को बड़ी स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी। अभियान के तहत भेजे जा रहे पोस्टकार्ड में नगीना में एम्स स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की उपलब्धता का उल्लेख किया गया है। बिजनौर रोड स्थित वर्षों से बंद पड़ी नगीना सहकारी कटाई मिल की जमीन को इसके लिए उपयुक्त बताया गया है। साथ ही सड़क और रेल मार्ग से बेहतर संपर्क तथा मुरादाबाद मंडल और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों की बड़ी आबादी को लाभ मिलने का तर्क भी दिया गया है। अभियान के संयोजक डॉक्टर भूषण चौहान ने बताया कि एक लाख पोस्टकार्ड भेजने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत पहले दिन एक हजार पोस्टकार्ड से की गई। पूर्व में इस संबंध में एसडीएम विजय शंकर मिश्रा को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। इस अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की तैयारी है। शुरुआत सरोज देवी ने पहला पोस्टकार्ड भेजकर की।

कारखाना अधिनियम 1948 : बनारस की बीड्स कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग हुई संपन्न



बनारस (शिखर समाचार)। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-अ के अनुपालन में बनारस बीड्स में फर्ट एंड वेलथ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सम्पन्न हुई, जिसमें एसएमई गुरुकुल फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से डॉक्टर अभिषेक कंचन ने कंपनी के सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में जानकारी दी। कार्यस्थल पर काम करते समय किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिये, जिससे कंपनी परिसर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने से बचा जा सके। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 111-अ के तहत कारखाने के नियोजता की जिम्मेदारी है कि वह कारखाने में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रशिक्षण दिलाए। मुख्य निरीक्षक कारखाना द्वारा अनुमोदित किसी प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण दिलाए, जो कार्यस्थल पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण देते हैं। यह भी आवश्यक होगा कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की वार्षिक विवरण क्षेत्र के फैक्ट्री डिपार्टमेंट के कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना अनिवार्य है अन्यथा कंपनी के ऊपर दंड के भी प्रावधान हैं।

Akshwani Civil Wing Sehkhari Awes Samiti Limited
Site Office: Akash Vihar, Park No. 1, Village Sadullabada, Loni, Ghaziabad (UP)
मौजू/2026/गाजियाबाद/आसपास/03/00/समितियों/03 दिनांक: 20.04.2026

सर्वसम्मति के साथ प्रबन्ध कमेटी के निर्णय के अनुसार सम्बन्धित सदस्यों को समय - समय पर बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया था परन्तु सदस्यों द्वारा कोई भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ और न ही समिति कार्यालय में आकर उक्त के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट किया जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित सदस्यों को अन्तिम नोटिस स्वीड पोस्ट के माध्यम से कई बार समिति द्वारा भेजा गया तथा उसने अन्तिम नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर जवाब देने का अनुरोध भी किया गया है लेकिन फिर भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ अन्त में यह निर्णय लिया गया कि इसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त करने की सूचना उनके सभी सम्बन्धित पते पर स्वीड पोस्ट के द्वारा भेजी गई फिर भी डिफाल्टर सदस्यों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया। अतः प्रबन्धक कमेटी में दिनांक 28.03.2026 को हुई अपनी बैठक के प्रस्ताव सं. 10 के माध्यम से उनकी सदस्यता समाप्त का निर्णय लिया गया एवं मध्यम में यदि सम्बन्धित सदस्य पुनर्वापस के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करते हैं तो प्रबन्ध समिति के उक्त के सम्बन्ध में कोई संज्ञान नहीं लेगी जिसकी सभी जिम्मेदार सदस्यों की स्वयं की होगी। सदस्यों की सूची विवरण अनुसार निम्न प्रकार है -

1- श्री एनओ साई राम - सदस्य सं. 04/AV/C/91
2- श्रीमती अनीता मल्होत्रा - सदस्य सं. 338/AV/97
3- श्रीमती हरविन्दर कौर - सदस्य सं. 342/AV/97
4- श्री तनुज नामपाल - सदस्य सं. 345/AV/97
5- श्री जतिन्धर कुमार निगम - सदस्य सं. 355/AV/97
6- श्री धीरेन्द्र कुमार - सदस्य सं. 360/AV/97

टाइगर गंगा हेरिटेज के नाम से रोडवेज की विशेष बस सेवा शुरू होगी



बिजनौर (शिखर समाचार)। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी जसजीत कौर ने की। बैठक में जनपद में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टाइगर गंगा हेरिटेज के नाम से परिवहन निगम की विशेष बस सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। यह सेवा क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक सिद्ध होगी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विकास कुमार अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष द्वारा जिले में प्लाई ऐश आधारित उत्पादों का निर्माण करने वाली औद्योगिक इकाइयों के हित में ईट प्रकरण की अनुसूची दरों में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्लाई ऐश ईट एवं टाइल्स की दरें निर्धारित किए जाने के अनुरोध पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पोर्टल पर प्राप्त 578 आवेदन पत्रों में से 227 का प्रथम स्तर पर सत्यापन, 108 का द्वितीय स्तर पर सत्यापन तथा 85 आवेदन तृतीय स्तर पर स्वीकृत पाए गए। वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत 1700 आवेदन के लक्ष्य के सापेक्ष 441 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमें से 13 स्वीकृत, 22 में ऋण वितरण, 428 लॉन्ग तथा 11 आवेदन बैंकों द्वारा अस्वीकृत पाए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रण विजय सिंह, उपायुक्त उद्योग अमित कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, विकास कुमार अग्रवाल, जलकुकार आलम, मुनीशा त्यागी, नितिन अग्रवाल तथा अन्य उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु उपस्थित रहे।

शादी से इनकार पर सनकी प्रेमी ने युवती की चाकू मारकर हत्या

बिजनौर (शिखर समाचार)। थाना शहर कोतवाली क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी में मंगलवार को प्रेम प्रसंग के चलते एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई। एक शादीशुदा युवक ने शादी से इनकार करने पर अपनी प्रेमिका की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काशीराम कॉलोनी निवासी कशिश का प्रेम प्रसंग दूसरे समुदाय के राहुल नामक युवक के साथ चल रहा था, जो पहले से विवाहित है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कशिश की मां किसी कार्य से घर से बाहर गई हुई थी। इसी दौरान राहुल वहां पहुंच गया और कशिश पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। कशिश द्वारा उसके शादीशुदा होने के चलते विवाह से इनकार करने पर राहुल आपा खो बैठा। गुस्से में आकर उसने पास में रखे चाकू से कशिश पर ताड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर रूप से घायल कशिश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और मामले में कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।



जीडीए का ओटीएस 2026 धमाका: डिफॉल्टर आवंटियों को बड़ी राहत, ब्याज जुमाने से मिलेगी मुक्ति



आरव शर्मा
गाजियाबाद (शिखर समाचार)। गाजियाबाद डिफॉल्टर (जीडीए) ने डिफॉल्टर आवंटियों के लिए खजाना खोल दिया है। लंबे समय से ब्याज और जुमाने की मार झेल रहे आवंटियों के लिए अब वन टाइम स्टेलमेंट (ओ टी एस) स्कीम का रास्ता साफ हो गया है। जीडीए ने युद्ध स्तर पर इस योजना को धरातल पर उतार दिया है।
क्या है योजना और क्यों है



खास ?
सरकार का सीधा मकसद है डिफॉल्टर्स को राहत देना और अटके हुए राजस्व को वापस लाना। जीडीए ने इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। शहर की हर गली से लेकर प्रमुख चौराहों तक, होर्डिंग्स, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए ओटीएस 2026 का शोर है।
हेल्थ डेस्क पर उमड़ी भीड़
जीडीए परिसर में 18 अप्रैल 2026 को विशेष ओटीएस हेल्थ डेस्क की शुरुआत की गई है। यहाँ सिर्फ नियमों की जानकारी ही नहीं दी जा रही, बल्कि धड़ाधड़ फॉर्म भी बांटे जा रहे हैं।
आंकड़ों की जुबानी:
पहले ही दिन से आवंटियों का तांता लगा है। अब तक लगभग 100 लोगों ने फॉर्म लिया है, जिसमें से 12 आवेदनकर्ता तो फॉर्म भरकर जमा भी कर चुके हैं।
डेडलाइन का रखें ध्यान
यह योजना सीमित समय के लिए है। योजना शुरू: 18 अप्रैल 2026

खतौली तहसील बार एसोसिएशन चुनाव संपन्न, सुभाष चन्द अध्यक्ष व सत्यप्रकाश सैनी महासचिव निर्वाचित

खतौली/मुजफ्फरनगर (शिखर समाचार)। खतौली तहसील बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर सुभाष चन्द तथा महासचिव पद पर सत्यप्रकाश सैनी निर्वाचित हुए। चुनाव में सभी 100 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे अधिवक्ताओं में उत्साह देखने को मिला। मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे प्रारंभ होकर दोपहर 1 बजे तक चली, जबकि मतगणना दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर देर शाम तक पूर्ण हुई। वरिष्ठ समिति के अध्यक्ष चतुराल सिंह तथा सदस्य रामचंद्र सैनी और मोहम्मद अरशद ने परिणामों की घोषणा की। अध्यक्ष पद के लिए हुए मुकाबले में सुभाष चन्द को 54 मत प्राप्त हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी सरदार जितेंद्र सिंह को 48 मत मिले। इस प्रकार सुभाष चन्द ने 6 मतों के



अंतर से जीत दर्ज की। महासचिव पद पर त्रिकोणीय मुकाबला काफी रोचक रहा, जिसमें सत्यप्रकाश सैनी को 44 मत, महेश कुमार को 39 मत तथा अनुज कुमार को 16 मत प्राप्त हुए। इस करीबी मुकाबले में सत्यप्रकाश सैनी ने 5 मतों से जीत हासिल की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नवाब सिंह को 54 मत तथा वेदप्रकाश उपाध्यक्ष को 44 मत मिले, जिसमें नवाब सिंह ने 10 मतों से विजय प्राप्त की। महिलाओं के लिए आरक्षित कोषाध्यक्ष पद पर अनामिका को 56 मत तथा शकुंतला को 43 मत प्राप्त हुए, जिसमें अनामिका विजयी रहीं। उपाध्यक्ष (10 वर्ष) के दो पदों पर गंगा शरण और मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष (8 वर्ष) के दो पदों पर हरिनवास और अशोक सैनी निर्वाचित हुए। महासचिव के तीन पदों पर रेखा देवी, युगांक मित्तल और विनोत कुमार गौतम ने जीत दर्ज की। वरिष्ठ सदस्य के छह पदों पर राजवीर सिंह, सचिन कुमार आर्य, अमित त्यागी, शक्तिर अहमद, विपिन कुमार और विकास कुमार निर्वाचित हुए।

कनिष्ठ सदस्य के छह पदों पर रवि कुमार, अभिषेक भड़ाना, तरुण मोघा, पंकज कुमार, अमन कुमार और अजय राठी विजयी रहे। वहीं अंकुश कुमार तथा एक अन्य प्रत्याशी को समान मत प्राप्त होने के कारण दोनों को छह-छह माह का कार्यकाल दिया जाएगा। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और मालाएं पहनाकर जीत का जश्न मनाया। जीत के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभाष चन्द ने इसे अधिवक्ताओं के विश्वास और सम्मान की जीत बताया और कहा कि वे अधिवक्ताओं के हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। वहीं महासचिव बने सत्यप्रकाश सैनी ने अपनी जीत को अधिवक्ताओं की एकजुटता का परिणाम बताया हुए सभी का आभार व्यक्त किया।

सक्षिप्त समाचार

केवाईसी न होने पर नहीं मिलेगा टैबलेट-स्मार्टफोन

वाराणसी। बीएचयू में जिन छात्र या छात्राओं ने डीजी शक्ति पोर्टल पर अपनी केवाईसी नहीं की है। उसे टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं मिल पाएगा। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के डीन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि छात्र और छात्राएं जल्द अपना केवाईसी कर लें। ताकि उन्हें लाभ मिल सके।

सीएम योगी ने गूलर रोड की घटना पर मेयर और नगर आयुक्त को किया तलब



अलीगढ़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गूलर रोड पर ऊंची-नीची सड़क के कारण हुए जानलेवा हादसे का संज्ञान लिया है। उन्होंने मेयर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त प्रेमप्रकाश मीणा को रिवार को लखनऊ लंबा किया और पूरी घटना की जानकारी ली। ऐसे हादसे दोबारा नहीं होने देने की सख्त हिदायत दी। बता दें कि बीते शुक्रवार की रात गूलर रोड पर ऊंची-नीची सड़क के कारण प्रतिभा कॉलोनी निवासी विकास कुमार राठौर की जान चली गई थी। मुख्यमंत्री ने मेयर और नगर आयुक्त से कहा कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। सभी निर्माणाधीन सड़कों के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएं। बैरीकेडिंग और ग्लोसाइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि रात के समय भी लोगों को सही स्थिति दिखाई दे सके और वह हादसों से बच सकें। मेयर प्रशांत सिंघल ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार सोमवार से सभी निर्माणाधीन सड़कों और अन्य प्रोजेक्ट के आसपास बैरिकेडिंग लगाई जाएगी। ग्लोसाइन बोर्ड लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सीएम से इंडोर स्टैडियम और अन्य प्रोजेक्ट के लोकार्पण का आग्रह किया गया है। इसके लिए जल्द ही उनके कार्यालय से समय मिलने की उम्मीद है।

1834 परीक्षार्थियों ने छोड़ी बीटेक, बीआरक की प्रवेश परीक्षा

अलीगढ़, एजेंसी। एएमयू की बीटेक, बीआरक की प्रवेश परीक्षा में 1834 और बीकॉम व बीबीए की प्रवेश परीक्षा में 474 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षाएं अलीगढ़, लखनऊ, प्रटना, कोलकाता, श्रीनगर और कोझिकोड सहित विभिन्न केंद्रों पर हुईं। सुबह की पाली में बीटेक, बीआरक की प्रवेश परीक्षा में पंजीकृत 14,405 में से 12,571 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। दूसरी पाली में बीकॉम, बीबीए की प्रवेश परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 3,813 में से 3339 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। कुलवार्ति प्रो. नईमा खातून ने प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद नवेद खान के साथ विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर, परीक्षार्थियों की सहायता के लिए एएमयू राष्ट्रीय सेवा योजना ने रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों पर विशेष हेल्प सेंटर स्थापित किए थे। साथ ही गैर-सरकारी संगठनों, छात्रों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने पेयजल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शिविर भी लगाए।

डीएवी के अर्थशास्त्री ने रिफाइनरी

स्थापना के लिए रिसर्च कर जुटाया डेटा

वाराणसी, एजेंसी। बीएचयू के संबद्ध कॉलेज डीएवी पीजी कॉलेज के रिसर्च आउटपुट के अनुसार राजस्थान के बालोतरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) परियोजना लगने जा रही है। डीएवी के अर्थशास्त्री प्रो. अनूप मिश्रा के नेतृत्व में बनी टीम ने यह पाया कि रिफाइनरी क्षेत्रीय विकास के हर पैमाने पर सफल है। अब राष्ट्र को समर्पित होने के लिए तैयार है। साल 2023 में एचपीसीएल ने इस परियोजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के आकलन के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण कराया था। इसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रो. मिश्रा को दी गई थी। डॉ. सिद्धार्थ सिंह और डॉ. उदयभान सिंह सहित 10 शोधकर्ताओं की टीम ने मई-जून 2023 में पंचपदरा क्षेत्र का दौरा कर डेटा जुटाया। फरवरी 2026 में किए गए हालिया अवलोकन से यह सामने आया कि अध्ययन के दौरान दिए गए लगभग 90 प्रतिशत सुझावों को धरतल पर सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इस परियोजना का लोकार्पण करेंगे। अध्ययन के अनुसार, रिफाइनरी के निर्माण के दौरान 24,000 से ज्यादा लोगों को सीधा रोजगार मिला। भविष्य में संचालन चरण में लगभग 10,000 और अक्सर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही 35,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे कुल मिलाकर 60,000 से 70,000 परिवारों की आजीविका इस परियोजना से जुड़ गई है। आर्थिक मोर्चे पर, स्थानीय निवासियों की औसत वार्षिक आय में भारी वृद्धि हुई है, जिससे बालोतरा का बाजार अब 250 से अधिक नई दुकानों और विकसित सेवा क्षेत्र के साथ एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है।

गर्मी से घबक रहा यूपी

ताजनगरी आगरा में पारा 43.6 डिग्री, आज से लू का रेड अलर्ट

आगरा, एजेंसी। ताजनगरी में भीषण गर्मी ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। 43.6 डिग्री सेल्सियस के साथ रविवार सोजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं न्यूनतम पारा 24 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी का असर पर्यटन पर भी देखने को मिला। आम दिनों में वीकेंड पर ताज का दीदार करने 40 हजार से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन रविवार को यह आंकड़ा महज 16,645 पर सिमट गया। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। लोगों के साथ पशु-पक्षी भी बेहाल दिखे।

मौसम विज्ञान विभाग ने आगरा और आसपास के क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 20 अप्रैल से क्षेत्र में तीव्र हीटवेव (लू) चलने की आशंका है। अगले तीन दिनों तक गर्म पछुआ हवाएँ लोगों को सताएंगी। सूखी गर्मी के कारण डेहलडूशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच बेवजह बाहर न निकलने की सलाह दी है।

भीषण गर्मी और तपिश के कारण दोपहर के समय ताजमहल परिसर के मुख्य हिस्सों में सन्नाटा पसरा नजर आया। रॉयल गेट से लेकर सेंट्रल टैंक तक पर्यटकों की संख्या बेहद कम रही। खास बात यह रही कि सेंट्रल टैंक स्थित डायना बेंच, जहां फोटो खिंचवाने के लिए पर्यटकों में होड़ मची रहती है और लंबी कतारें लगती हैं, रविवार दोपहर वहां पर्यटकों की संख्या बेहद कम रही। चिलचिलाती धूप के कारण पर्यटक स्मारकों में घूमने के बजाय छायादार जगहों की तलाश करते नजर आए। आगरा किला और अन्य स्मारकों पर भी पर्यटकों की संख्या बेहद कम रही।



य्यासे रहे पर्यटक, बंद मिले दोनों आरओ प्लांट ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास पर्यटकों की सुविधा के लिए दो आरओ प्लांट लगाए गए हैं, लेकिन रविवार को ये दिखावा साबित हुए। भीषण गर्मी में जब पर्यटकों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दोनों ही प्लांट बंद पड़े थे। इसके चलते पर्यटकों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा और मजबूरी में महंगी बोतलों का सहारा लेना पड़ा।

धरी रह गई नोटशीट की कहानी, साथ ही दिखने लगे गुनाह और चुस्त महकमे में सुस्त फाइलों के किस्से

लखनऊ, एजेंसी। यूपी के राजनीतिक गलियारों और प्रशासनिक गलियारों में आज तीन किस्से काफी चर्चा में रहे। चाहे-अनचाहे आखिर ये बाहर आ ही जाते हैं। इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम होती है। आज की कड़ी में धरी रह गई माननीयों की नोटशीट की कहानी। इसके अलावा टैपड ग्लास से दिखने लगे गुनाह और चुस्त महकमे में सुस्त फाइलों के किस्से भी चर्चा में रहे।

धरी रह गई माननीयों की नोटशीट: आधी आबादी के मुद्दे पर हुई प्रेसवार्ता में एकता दिखाने के लिए बुलाया तो गया था सभी घटक दलों के माननीयों को लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। हालांकि, माननीयों की तैयारी में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पूरी तन्मयता से हर बिंदु पर नोट बनाए थे, ताकि मौका मिलेगा तो बांचेंगे भी। उनकी बोलने की बेताबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि घटक दलों के सभी माननीय मंच पर मुखिया के संबोधन पर कम और अपने नोट तैयार करने में ज्यादा मशगूल दिखे। उन्हें भरोसा था कि बार-बार घटक दलों की एकता की बात हो रही है तो बोलने का मौका भी मिलेगा, लेकिन उनके हिस्से आई सिर्फ निराशा। लिहाजा प्रेसवार्ता खत्म होने की घोषणा होते ही सभी माननीय मन मसोस कर निकल गए।

टैपड ग्लास से दिखने लगे गुनाह: एक जिले में डीएम पर तहसीलदार ने घूस के आरोप क्या जड़े, हमेशा की तरह आई एम सेंफ बिरादरी ने तहसीलदार को ही गुनहारा बताकर निपटाने की तैयारी कर ली। सारा मामला सही चल रहा था लेकिन फोन पर टैपड ग्लास लगाकर देने की मांग वाली ऑडियो क्लिप ने साहब की बेगुनाही से पर्दा हटा दिया। ऑडियो में पौने दो लाख के आईफोन के साथ टैपड ग्लास भी लगे हुए थे।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पर 23 अप्रैल को लगेगी पासपोर्ट लोक अदालत



गाजियाबाद (शिखर समाचार)।

पासपोर्ट संबंधित समस्याओं और आवेदकों की लंबित फाइलों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद पर पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से पासपोर्ट से सम्बंधित लंबित फाइलों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। पासपोर्ट लोक अदालत आगामी 23 अप्रैल 2026 को शाम 3 बजे से 5 बजे तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय हापुड़ चुंगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद के कक्ष संख्या 320 में आयोजित की जाएगी। इस अदालत में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी आवेदकों से मिलकर उनकी समस्याएँ सुनेंगे और निस्तारण करेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी अनुज स्वरूप ने बताया कि विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद इस विशेष पासपोर्ट लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। समय की सीमित उपलब्धता के कारण अदालत में 50 आवेदकों की फाइलों का निस्तारण किया जाएगा। इन्होंने नागरिकों से अपील कि आवेदक अपने साथ सम्बंधित दस्तावेज व मूल प्रतिय एवं छायाप्रति लेकर आएँ और इस आयोजन का लाभ उठाएँ, जिससे उनकी समस्या का सरलता से निस्तारण किया जा सके।

अक्षय तृतीया ने तोड़ दिया सोने-चांदी के भाव का भ्रम

बाजार में हुई इतनी खरीद, खिल उठा कारोबार

आगरा, एजेंसी। अक्षय तृतीया पर्व पर रविवार को बाजारों में जबरदस्त रौनक लौट आई। सोने-चांदी के आभूषणों से लेकर सिक्के और बर्तन खूब बिके। रियल एस्टेट से लेकर कपड़ा और वाहन बाजार तक में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान शहरभर में करीब 100 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है। ग्राहकों का यह उत्साह सोमवार को भी जारी रहने की उम्मीद है।

एमजी रोड से लेकर किनारी बाजार तक ज्वेलरी शोरूम पर भारी भीड़ रही। किनारी बाजार, खयत पाड़ा और जौहरी बाजार में खरीदारी के लिए ग्राहक उमड़ पड़े। सोने और चांदी की रिकॉर्ड बिक्री ने व्यापारियों को गदगद कर दिया। आभूषण ज्वेलर्स के स्वामी आनंद अग्रवाल ने बताया कि मेकिंग चार्ज पर भारी छूट और निश्चित उपहारों जैसे शानदार ऑफर्स के कारण ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की। हल्के गहनों के साथ-साथ निवेश के लिए सिक्कों और बुलियन की भी भारी मांग रही। हमारे यहां निश्चित खरीद पर चांदी के सिक्के भी मुफ्त बांटे गए हैं। ग्राहकों के लिए ये ऑफर्स सोमवार को भी जारी रहेंगे।

विवाह सीजन से अन्य सेक्टरों में भी भारी उछाल: शादी के सीजन के चलते केवल सरीफा बाजार ही नहीं, बल्कि अन्य व्यापारिक क्षेत्रों में भी



रविवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली।

कपड़ा और गारमेंट बाजार: शान्ति के मुख्य खरीदारी के कारण गारमेंट शोरूम और सुभाष बाजार स्थित थोक कपड़ा बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ रही।

ऑटोमोबाइल सेक्टर: शुभ मुहूर्त पर दोपहिया और चार पहिया वाहनों की जमकर बिक्री हुई। शोरूम पर पहले से बूक किए गए वाहनों की डिलीवरी लेने वालों का तांता लगा रहा।

रियल एस्टेट: निवेशकों और घर खरीदारों ने भी इस पावन अवसर पर रियल एस्टेट में भारी दिलचस्पी दिखाई। संपत्तियों की जमकर बिक्री हुई और कई लोगों ने नए घर में गृह प्रवेश भी किया।

बर्तन बाजार: परंपरा के अनुसार अक्षय तृतीया पर धातु खरीदना शुभ माना जाता है, जिसके चलते बर्तन बाजार में भी अच्छी-खासी बिक्री दर्ज की गई।

आज भी अच्छे कारोबार की आस: आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल का कहना है कि अक्षय तृतीया का यह व्यापारिक उत्साह अभी थमा नहीं है। ऑफर्स की मियाद और ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए सोमवार को भी बाजारों में अच्छी खरीदारी होने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर, ग्राहकों के उत्साह और ऑफर्स की बारिश ने इस बार अक्षय तृतीया को व्यापारिक जगत के लिए बड़ी सफलता बना दिया है।

लायंस क्लब शामिल सेनेजी ने किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

शामली (शिखर समाचार)। लायंस क्लब शामली सेनेजी द्वारा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और हरित वातावरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक भव्य पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रॉक गोल्ड एकेडमी परिसर में संपन्न हुआ।

मंगलवार को क्लब के सदस्यों ने परिसर में कई छायादार एवं फलदार पौधों का रोपण किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पौधारोपण से क्षेत्र में हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है।

सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण को वर्तमान समय की सबसे बड़ी जरूरत बताते हुए सभी से इसमें सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। साथ ही उपस्थित



लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी निर्यात देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में परियोजना अध्यक्ष प्रियंका

गोयल, सिद्धार्थ गर्ग, विश्वास, तुषार धवन, वैभव गुप्ता, मोहित कंबोज और पुनीत जैन सहित अन्य सदस्यों ने सहभागिता की।

कांधला के बीपीएन जूनियर हाई स्कूल पहुंचे अभिनेता राहुल राय, बच्चों के साथ बिताया समय

शामली (शिखर समाचार)।

राहुल राय ने मंगलवार को कांधला स्थित बीपीएन जूनियर हाई स्कूल का दौरा कर विद्यार्थियों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया, उनसे संवाद किया और उनकी रचनात्मक गतिविधियों को ध्यानपूर्वक देखा। विद्यालय के बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किए गए सुंदर कार्ड भेंट कर उनका स्वागत किया, वहीं पुष्प अर्पित कर सम्मान जताया। जनपद के एक दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे राहुल राय ने विद्यार्थियों की प्रतिभा की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि छोटे कर्बों में भी बच्चों में कड़ी मेहनत, लगन और हुनर की कमी नहीं है, जो देश के भविष्य के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है। उन्होंने बच्चों को निरंतर प्रयास करते रहने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित



किया। विद्यालय की संचालन समिति की अध्यक्ष अलका चौहान, जनेश्वर चौहान और प्रबंधक श्वेता चौहान ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रधानाचार्या शमा प्रवीण ने अभिनेता को विद्यालय परिसर का भ्रमण कराया और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्बाई क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद विद्यालय विद्यार्थियों को

आधुनिक और उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस मौके पर कुशांक चौहान, परग जैन, अजय जैन, अमन मिर्जा, विपिन चौहान, अजय चौहान, गोपाल चौहान, विनाद कश्यप, आराम चौहान, विनाद कश्यप, विकास सैनी और विशाल सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

अच्छी शिक्षा से 22 प्रतिशत कम होता है हार्ट फेल होने पर मौत का जोखिम

लखनऊ, एजेंसी। अच्छी शिक्षा सिर्फ करिअर ही नहीं बनाती, हार्ट फेल होने पर जान जाने का जोखिम भी 22 फीसदी तक कम करती है। भारतीय राष्ट्रीय हृदय विफलता रजिस्ट्री (एनएचएफआर) के अध्ययन में यह बात सामने आई है। इसे ओपन हार्ट पत्रिका के अप्रैल के अंक में स्थान मिला है।

एनएचएफआर के अध्ययन में भारत के 21 राज्यों के 53 अस्पतालों से हार्ट फेलियर के 10,850 मरीजों को शामिल किया गया था। हार्ट फेल के बाद एक वर्ष तक इनकी निगरानी की गई। इसके आधार पर मृत्यु दर का आकलन किया गया। मधुमेह से पीड़ित मरीजों में मधुमेह रहित मरीजों की तुलना में मृत्यु का जोखिम 10 फीसदी अधिक पाया गया। अध्ययन में यह भी देखा गया कि मधुमेह से पीड़ित उच्च शिक्षित मरीजों में मृत्यु का जोखिम 22 फीसदी कम था, जो शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। वहीं, मधुमेह पीड़ित और कम शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले मरीजों में मृत्यु का जोखिम बाकी लोगों की तुलना में 25 फीसदी अधिक पाया गया।

अध्ययन में ये रहे शामिल: डॉ. प्रतियामकल जीमोन, डॉ. सुनु थॉमस, डॉ. अजय बहल, डॉ. अंबुज राय, डॉ. अनिमेष मिश्रा, डॉ. जयेश प्रजापति, डॉ. मंजूनाथ



सी नंजप्पा, डॉ. ऋषि सेठी, डॉ. सांतनु गुहा, डॉ. सतीश संतोष, डॉ. रूचिंद्र एस धालीवाल, डॉ. मीनाक्षी शर्मा, डॉ. संजय गणपति, डॉ. गिरीश पलेड़ा, डॉ. नीरव कुमार, डॉ.

सुशील मालानी, डॉ. प्रकाश नेगी, डॉ. आदित्य कपूर, डॉ. धर्मेन्द्र जैन, डॉ. संदीप चौधरी, डॉ. स्मित श्रीवास्तव, डॉ. बलबीर सिंह यादव, डॉ. सिवादासनपिह्लै हरिकृष्णन।

अध्ययन में पाया गया कि हार्ट फेल होने के बाद एक वर्ष के भीतर 22.1 फीसदी मरीजों की मौत हो गई। इनमें भी मधुमेह पीड़ित और कम शिक्षित रोगियों का प्रतिशत ज्यादा था।

बर्तने से सावधानी

वजन न बढ़ने दें, नमक का सेवन कम करें, संतुलित आहार लें, समय पर दवाएं लें, पल्लू और निर्मानिया के टीके लगावाएं, डॉक्टर की सलाह से हल्का व्यायाम करें या टहलें, धूम्रपान और शराब बंद करें, तनाव न लें।

इसलिए अहम है शिक्षा

केजीएमयू में कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रो. ऋषि सेठी ने बताया कि हार्ट फेल होने के बाद दवाओं के साथ ही जीवनशैली में बड़े बदलाव की जरूरत होती है। समस्या होने पर लक्षणों को पहचान कर डॉक्टर के पास जाना होता है। इन सभी में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यह बात इस अध्ययन में भी सामने आई है।

जानें, कब करें डॉक्टर से संपर्क

सांस लेने में भारी कठिनाई, सोने में दर्द, वजन में तेजी से वृद्धि, पैरों या पेट में सूजन होने पर।

श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए डीएम ने अधिकारियों संग की बैठक, माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। जनपद में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनकी दैनिक समस्याओं के प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि



श्रमिकों के कार्यस्थलों, आवासीय क्षेत्रों और निर्माण स्थलों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाए और उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य शिविर

श्रमिकों की सुविधा के अनुसार आयोजित हों, ताकि उन्हें सुलभ और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। शिविरों में चिकित्सकों की उपलब्धता, आवश्यक दवाइयां, जांच सुविधाएं और टेलीमैडिसिन जैसी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से



सुनिश्चित की जाएं। इसके साथ ही फर्स्ट एड, रक्तदान, आपदा प्रबंधन और हेल्थ वेलनेस सेंटर्स को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार

किया जाए और जागरूकता अभियानों के माध्यम से अधिक से अधिक श्रमिकों को इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए। बैठक में औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों के लिए एनजीओ के सहयोग से सस्ती

और पौष्टिक भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्राथमिकता से समन्वय स्थापित कर इस व्यवस्था को जल्द लागू किया जाए।

बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा लक्ष्मी वीएस, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अजय राणा, उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, एसएमओ रविंद्र सिरोहा, चंदन सोनी, मंजीत सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी आरपी सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर ने संभाली कमान, व्यापारियों की सुरक्षा व साइबर सतर्कता पर दिए सख्त निर्देश

मुजफ्फरनगर (शिखर समाचार)। जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार को रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में आयोजित व्यापारी सुरक्षा गोष्ठी में नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर ने स्वयं उपस्थित होकर व्यापारियों की समस्याएं सुनीं और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए। गोष्ठी की अध्यक्षता नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर तथा पुलिस अधीक्षक अपराध इंद्रु सिद्धार्थ ने की। नगर मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि बाजारों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही व्यापारियों से भी अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे



लगाएँ, उनकी दिशा सही रखें और बाजार स्तर पर आपसी समन्वय बनाकर अतिरिक्त कैमरों की व्यवस्था करें। राठौर ने विशेष रूप से रात्रि के समय बाजारों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सामूहिक सुरक्षा गार्ड या चौकीदार की व्यवस्था करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में नकदी के परिवहन से पूर्व स्थानीय पुलिस को सूचना देना अनिवार्य किया जाए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी जाए। बैठक में साइबर अपराधों को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। नगर मजिस्ट्रेट ने व्यापारियों को जागरूक करते हुए कहा कि ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए सतर्क रहना अत्यंत

आवश्यक है। किसी भी अनजान कॉल, लिंक अथवा ओटीपी साझा करने से बचें। उन्होंने साइबर सहायता हेल्पलाइन 1930 के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए आवश्यकता पड़ने पर तत्काल शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए। गोष्ठी में अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, थाना प्रभारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग तथा यातायात विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और व्यापारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया गया, ताकि जनपद की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

हापुड़ (शिखर समाचार)। जनपद की नवनिर्गम जिलाधिकारी कविता मीना ने मंगलवार सायंकाल कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कोषागार पहुंचकर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ परिचय बैठक की और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके बाद अपने कार्यकक्ष में पहुंचकर उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित किया और अपनी कार्य प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। ज्ञातव्य है कि पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक पांडे का शासन द्वारा सोमवार सायंकाल स्थानांतरण कर दिया गया था। उनके स्थान पर मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष रहती कविता मीना को हापुड़ का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचने पर उन्हें सम्मान स्वरूप गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके पश्चात उन्होंने कोषागार में पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान



प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि जनपद के समग्र विकास को गति देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और इसके लिए सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर टीम भावना के साथ कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, आमजन तथा मीडिया के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना आवश्यक है, जिससे शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके और जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में संचालित विकास कार्यों को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और जो योजनाएं प्रगतिशील हैं, उन्हें

प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाएगा। सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसे पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निभाया जाएगा। जिलाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए उनका कार्यालय सदैव खुला रहेगा और प्रत्येक नागरिक की शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए उसका सम्यक् न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें और शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को गति प्रदान करें।

युवा उद्यमियों के बीच संपन्न हुआ एक दिवसीय मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच



हापुड़ (शिखर समाचार)। इंडियन यंगप्रेन्योर सेल के तत्वावधान में युवा उद्यमियों के बीच एक दिवसीय मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन दिल्ली रोड स्थित मैदान पर किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैच के दौरान कप्तान वैभव गुप्ता एवं उपकप्तान मुदित बंसल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को शारीरिक रूप से सक्रिय बनाए रखना, आपसी सहयोग की भावना को मजबूत करना तथा एक-दूसरे से नई चीजें सीखने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के विकास में भी सहायक होता है। मैत्रीपूर्ण माहौल में खेले गए इस मुकाबले में सभी प्रतिभागियों ने खेल भावना का परिचय दिया और पूरे जोश के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। आयोजन के दौरान खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और उत्साह देखने लायक रहा। मैच में आयुष गर्ग, अक्षत अग्रवाल, आयुष गोयल, समर्थ अग्रवाल, ध्रुव गुप्ता, शिवम शर्मा, युजित मोहन, विभोर अग्रवाल, इंद्र मोहन बंसल, शांभु गोयल, पारित अग्रवाल, माधव, अभिनव, प्रशांत शर्मा, तन्मय आशीष एवं आदित्य सहित कई युवा उद्यमी शामिल रहे। आयोजन के अंत में सभी प्रतिभागियों ने ऐसे कार्यक्रमों को भविष्य में भी जारी रखने की सहमति व्यक्त की।

बीएसए के निरीक्षण में दो कंपोजिट विद्यालय मिले बंद, दो अवैध स्कूलों को नोटिस



हापुड़/धौलाना (शिखर समाचार)। जिले में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत उस समय सामने आई जब मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रीतु तोमर ने विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धौलाना ब्लॉक क्षेत्र के गांव लाखल और डिण्डालपुर में संचालित दो कंपोजिट विद्यालय निर्धारित समय से पहले बंद पाए गए। विद्यालयों के बंद बंद थे और बच्चे बाहर खेलेते हुए मिले, जिससे शिक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि लापरवाही बरतने पर दोनों विद्यालयों के प्रशासकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान पिलखुवा क्षेत्र में भी दो निजी विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जहां दोनों स्कूल बिना मान्यता के संचालित होते मिले। इतना ही नहीं, इन विद्यालयों में बच्चों को बैग और किताबें भी बेची जा रही थीं, जो नियमों के विरुद्ध है। बीएसए रीतु तोमर ने बताया कि दोनों अवैध रूप से संचालित विद्यालयों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नियमावली सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में बिना मान्यता के स्कूल चलाने और शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनगणना प्रशिक्षण के पहले दिन कई कर्मचारी रहे नदारद, कार्रवाई की तैयारी



सहारनपुर (शिखर समाचार)। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा जनगणना के प्रथम चरण की ट्रेनिंग का आयोजन राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और जीआईसी में कराया गया। यह प्रशिक्षण जनगणना निदेशालय के सहायक निदेशक आशुतोष की देखरेख में संपन्न हुआ। हालांकि पहले ही दिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अनुपस्थित रहे, जिससे अधिकारियों ने नाराजगी जताई और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। सहायक नगर आयुक्त विकास धर दुबे ने बताया कि कुल 460 कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित था, जिसमें 245 कर्मचारियों को राजकीय कन्या इंटर कॉलेज और 215 कर्मचारियों को जीआईसी में प्रशिक्षण दिया जाना था। बावजूद इसके, कई कर्मचारी बिना सूचना के अनुपस्थित रहे। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जनगणना अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई के लिए उनके विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण तीन दिवसीय है, जिसमें 22 और 23 अप्रैल को भी सत्र आयोजित किए जाएंगे। जो कर्मचारी पहले दिन अनुपस्थित रहे हैं, यदि वे शेष दो दिनों में प्रशिक्षण में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन लगातार अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान सहायक निदेशक आशुतोष के साथ जोन तीन के चार्ज अधिकारी विकास धर दुबे, जोन दो की चार्ज अधिकारी श्रुति महेश्वरी और सहायक चार्ज अधिकारी सुधीर शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में तहसील पर किसानों मजदूरों का उग्र प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

मोदीनगर (शिखर समाचार)। भारतीय किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में किसानों, मजदूरों और आम उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने के विरोध में तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के चार धरना देते हुए नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर आक्रांश व्यक्त किया। मोर्चा अध्यक्ष बबली गुर्जर, सत्येंद्र शर्मा, नीज प्रजापति और राहुल प्रधान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल रहीं। सभी प्रदर्शनकारी दिल्ली-मेरठ मार्ग से पैदल मार्च करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे और वहां पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूरे क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों की आवाज गूंजी रही। बबली गुर्जर ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने से किसान, मजदूर और निम्न व मध्यम वर्ग के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मीटरों

एमएसपी खरीद में एकरूपता के लिए राष्ट्रीय किसान डाटाबेस जरूरी: अशोक बालियान

मुजफ्फरनगर (शिखर समाचार)। मुजफ्फरनगर से उठी एक महत्वपूर्ण मांग में पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने केंद्र सरकार से देशभर में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कृषि उपज की खरीद के लिए राष्ट्रीय किसान डाटाबेस बनाने की अपील की है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के बीच फसल बेचने में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। बालियान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर एमएसपी खरीद व्यवस्था में एकरूपता लाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि एक रा्ट, एक बाजार की अवधारणा अभी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है, क्योंकि कृषि और मंडियों का संचालन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पत्र में उन्होंने बताया कि अलग अलग राज्यों में एमएसपी खरीद के नियम और पंजीकरण प्रक्रियाएं भिन्न हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश के किसान हरियाणा जैसे राज्यों के सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी फसल नहीं बेच पाते, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्त करने के अवसर सीमित हो जाते हैं। उन्होंने वर्ष 2020 के कृषि कानून, विशेषकर किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) अधिनियम का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय किसानों को मंडियों के बाहर और राज्यों की सीमाओं के पर फसल बेचने की स्वतंत्रता देने का प्रयास किया गया था। हालांकि ये कानून वापस ले लिए गए, लेकिन एक देश एक बाजार का लक्ष्य अब भी अधूरा है। बालियान ने सुझाव दिया कि एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया जाए, जो ई-नाम के अन्तर्गत ही कार्य करे। इसके माध्यम से किसान अन्य राज्यों की मंडियों में पहले से समय निर्धारित कर अपनी उपज बेच सकें। उन्होंने हरियाणा की मेरी फसल, मेरा ब्यौरा योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे अन्य राज्यों के किसानों के लिए भी खोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय किसान डाटाबेस तैयार होने से सभी किसानों का एकीकृत रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे वे देश के किसी भी हिस्से में एमएसपी पर अपनी उपज बेच सकेंगे। अंत में उन्होंने पारदर्शी अंतरराज्यीय व्यापार नीति लागू करने की मांग करते हुए कहा कि इससे राज्यों के बीच विवाद कम होंगे और किसानों को व्यापक बाजार मिलेगा।



शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में संस्था के कार्य, डायलिसिस मशीन चालू कराने की मांग



कांठला/शामली (शिखर समाचार)। दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक रेस्टोरेंट में संघटित सामाजिक सेवा संस्था द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। संजोयक एवं पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने बताया कि संस्था शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित क्षेत्र के आठ सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड लगाए गए। साथ ही 11 विद्यालयों में 2100 बच्चों के लिए कुर्सी-बेंच, 2000 स्कूल बैग, 3500 जर्सी और 33 साइकिल वितरित की गईं। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत कांठला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दो डायलिसिस मशीन और डेंटल चेयर उपलब्ध कराई गईं। इसके अलावा कई गांवों में स्वच्छ पेयजल के लिए स्टील टैंक और 15 ग्राम पंचायतों में कूड़ा प्रबंधन हेतु ई-रिक्शा दिए गए। बंसल ने बताया कि डायलिसिस मशीन तकनीशियन के अभाव में चालू नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विष्णु प्रकाश अग्रवाल ने की तथा संचालन मेहर चंद सिंघल व अमन मिश्र ने किया। कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

अंतरराष्ट्रीय जर्नल में आरके पीजी कॉलेज के एमएससी छात्र का शोध पत्र प्रकाशित

शामली (शिखर समाचार)। शहर के आरके पीजी कॉलेज के भौतिकी विभाग के लिए गर्व का विषय है कि एमएससी छात्र का शोध पत्र दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह उपलब्धि न केवल कॉलेज बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरके पीजी कॉलेज ने शोध और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. संजीव कुमार के मार्गदर्शन में एमएससी भौतिकी के छात्र आशुतोष शर्मा ने उच्च गुणवत्ता वाला शोध पत्र तैयार किया, जिसे विश्व प्रसिद्ध प्रकाशक सिंगर नेचर के जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में प्रकाशित किया गया है। इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 है, जो इसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। यह शोध पत्र विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभव आधारित अधिगम के उद्देश्य की सफलता को भी प्रदर्शित करता है। शोध में पाइथन आधारित मॉडलिंग के माध्यम से नैनोटेक्नोलॉजी को विस्तार से समझाया गया है। इसमें प्रोफेसर और कार्बन नैनो ट्यूब्स जैसे उन्नत पदार्थों के त्रिआयामी दृश्यांकन को सरल बनाया गया है, जिससे छात्रों को जटिल अवधारणाएं समझने में मदद मिलेगी। इस उपलब्धि से न केवल संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ी है, बल्कि क्षेत्र में शिक्षा और शोध के प्रति नई प्रेरणा भी मिली है।



नोटिसों का जवाब न देने पर 25 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। अपर श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर राकेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में श्रम कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों के कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं। इसके बाद विभाग की ओर से संबंधित संविदाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। लेकिन 25 संविदाकारों ने तय समय में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। अपर श्रमायुक्त ने बताया कि निरस्त किए गए संविदाकारों की सूची कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (पीएफ) को भेज दी गई है, ताकि वे अपने अपने कानूनों के तहत जांच कर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिभावक शिक्षक बैठक का सफल आयोजन

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। बिसरख ब्लॉक के बादलपुर सेक्टर स्थित तीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर अभिभावक-शिक्षक बैठक (पीटीएम) का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक पूजा तथा सुपरवाइजर विनोद कुमार ने सक्रिय भूमिका निभाई। बैठक में अभिभावकों को पीटीएम के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्हें जानकारी दी गई कि हर माह आयोजित होने वाली इन बैठकों में बच्चों के समग्र विकास, पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा की जाती है। इससे अभिभावकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है। इस माह की बैठक में नए बच्चों का स्वागत किया गया तथा पोषण पाठशाला के माध्यम से संतुलित आहार की जानकारी दी गई। साथ ही खेल आधारित गतिविधियों के जरिए बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर जोर दिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सामान में बच्चों की सीखने की क्षमता को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा रहा है। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गुरु, रुमी शर्मा, ममता, रेखा और उषा सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। अंत में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी ने मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।

बंद मकान में चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार



सहारनपुर/नानौता (शिखर समाचार)। थाना नानौता क्षेत्र के मोहल्ला कानूनीगोयान में बंद मकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहल्ला निवासी मोहम्मद अस्मर ने 18 अप्रैल को थाने में तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात चोर उनके घर का ताला तोड़कर लगभग 1.25 लाख रुपये के आभूषण और 73 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम ने 19 अप्रैल को इंदगाह के पास स्थित एक आम के बाग से युसुफ, सलमान और शुभम निवासी नानौता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सामान में पांच जोड़ी पाजेब, आठ अंगूठियां, दो छल्ले, एक चैन और 15,600 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यूसुफ के खिलाफ चोरी, शस्त्र अधिनियम और जीआ अधिनियम समेत करीब 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

संपादकीय

ईरान अमेरिका तनावनी : संवाद की अनिश्चित राह और वैश्विक संतुलन की चुनौती

पश्चिम एशिया एक बार फिर कूटनीतिक अनिश्चितताओं के भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया जाना कि उसने अभी तक अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह बयान केवल एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस गहरे अविश्वास और रणनीतिक दूरी का प्रतीक है, जो वर्षों से दोनों देशों के संबंधों में बनी हुई है। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, यह गतिरोध न केवल क्षेत्रीय बल्कि विश्व स्तर पर भी असर डाल सकता है।

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कोई नया विषय नहीं है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। 2015 में हुए परमाणु समझौते ने कुछ समय के लिए उम्मीद जगाई थी, लेकिन बाद में अमेरिका के उससे अलग होने और प्रतिबंधों को फिर से लागू करने से स्थिति और जटिल हो गई। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संवाद लगभग ठप हो गया। हाल के महीनों में यह उम्मीद जताई जा रही थी कि बदलते वैश्विक हालात और मध्यस्थ देशों की पहल के चलते बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ईरान के ताजा बयान ने इन संभावनाओं पर फिलहाल विराम लगा दिया है।

वर्तमान परिस्थितियों में ईरान का यह रुख कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, ईरान अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता को लेकर बेहद संवेदनशील है। वह किसी भी वार्ता में तब तक शामिल नहीं होना चाहता, जब तक उसे यह भरोसा न हो कि बातचीत बराबरी के आधार पर होगी और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। दूसरा, अमेरिका की नीतियों को लेकर ईरान में गहरा अविश्वास है, खासकर पिछले अनुबंधों के कारण। ऐसे में बिना स्पष्ट आश्वासन के वार्ता में शामिल होना ईरान के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है।

दूसरी ओर अमेरिका भी अपने रणनीतिक हितों के तहत ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है। आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य उपस्थिति और क्षेत्रीय गठबंधनों के जरिए वह ईरान को सीमित करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन यह नीति अब उतनी प्रभावी नहीं दिख रही, जितनी पहले थी। वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, और चीन के बढ़ते प्रभाव ने अमेरिका की प्राथमिकताओं को भी प्रभावित किया है। ऐसे में ईरान के साथ टकराव को कम करना अमेरिका के हित में हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी नीति में लचीलापन दिखाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल दो देशों तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया पहले ही कई संघर्षों और अस्थिरताओं का केंद्र रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से इस क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है, जिसका सीधा प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजार, व्यापार और सुरक्षा पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए, जो इस क्षेत्र से ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, यह स्थिति विशेष चिंता का विषय है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसके अलावा यह मुद्दा वैश्विक कूटनीति की विषयसूची पर भी सवाल उठाता है। यदि बड़े देश आपसी मतभेदों को संवाद के माध्यम से हल करने में असफल रहते हैं, तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक नकारात्मक संकेत है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों की भूमिका भी ऐसे समय में महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन उनकी प्रभावशीलता भी सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। फिलहाल यह स्पष्ट है कि ईरान और अमेरिका के बीच संवाद की यह आशा नहीं है। दोनों पक्षों को अपने अपने हितों में संतुलन लाना होगा। ईरान को जहां अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे, वहीं अमेरिका को भी अपनी नीतियों में भरोसा पैदा करने वाला बदलाव करना होगा।

मौलिक चिंतन

सच्चा ईशान हर एक में अपना जैसा सच्चा दिल तलाशता है और धोखा खाता है।



©
विनय
संगोची



कालिलाल मांडोंत

पिछले दो दशकों में अंतरिक्ष गतिविधियों में जिस तेजी से वृद्धि हुई है, उसने मानवता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, लेकिन इसके साथ एक गंभीर खतरा भी पैदा हो गया है। यह खतरा है अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ते मलबे का, जिसे अब वैज्ञानिक हार्स्पेस डेब्रिस के नाम से पहचानते हैं। 2005 से 2025 के बीच भारत सहित दुनिया के कई देशों ने सैकड़ों उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए, जिससे पृथ्वी की कक्षा पहले की तुलना में कहीं अधिक भंडारित वस्तुएं हो गई हैं। इस स्थिति ने सैटेलाइट की सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती बना दिया है।

भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए कई बार अपने उपग्रहों और मिशनों को संभावित टकराव से बचाने के लिए कक्षा में बदलाव किया है। हाल के वर्षों में उपग्रहों और चंद्र मिशनों को कुल 18 बार खतरे से बचाने के लिए रास्ता बदलना पड़ा, जिनमें से अधिकांश मामले अंतरिक्ष मलबे से जुड़े थे। यह केवल तकनीकी चुनौती नहीं है, बल्कि यह भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों



ललित गर्ग

मानव सभ्यता के विकास का इतिहास यदि देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हर नई तकनीक अपने साथ संभावनाओं और संकटों का एक द्वंद्व लेकर आती है। आज का समय भी इसी द्वंद्व से गुजर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में विकसित हो रही नवीन तकनीक ने जीवन को सरल, तीव्र और सुविधाजनक बनाया है, किंतु इसके साथ ही यह मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती भी बनकर उभर रही है। समाज के चिंतकों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक नेतृत्व ने समय-समय पर इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और हाल ही में पोप लियो 14 द्वारा व्यक्त आशंकाओं ने इस चिंता को वैश्विक विमर्श का केंद्र बना दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि इस तकनीक का उपयोग नैतिक मर्यादाओं से परे जाकर किया गया, तो यह विश्व में विभाजन, भय, हिंसा और संघर्ष को बढ़ावा दे सकती है। यह चेतावनी केवल एक धार्मिक नेता की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह उस गहरी चिंता का संकेत है जो आज पूरी मानवता के भीतर कहीं न कहीं विद्यमान है। तकनीक अपने आप में न तो नैतिक होती है और न ही अनैतिक, किंतु उसका उपयोग उसे किसी भी दिशा में ले जा सकता है।

वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग केवल रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों तक सीमित नहीं रह गया है। इसके माध्यम से झूठी सूचनाओं का निर्माण, नकली चित्रों और ध्वनियों का सृजन तथा जन्मत को प्रभावित करने के प्रयास तेजी से बढ़े हैं। चुनावी प्रक्रियाओं में इसका उपयोग लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है। जब कोई मतदाता यह

स्पेस में बढ़ता मलबा और सैटेलाइट की सुरक्षा बनी चुनौती

की सुरक्षा और सफलता से भी जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। अंतरिक्ष में मलबे की समस्या अब एक वैश्विक चिंता बन चुकी है। विभिन्न शोधों के अनुसार, पृथ्वी की कक्षा में 10 सैटीमीटर से बड़े लगभग 40,000 मलबे के टुकड़े मौजूद हैं, जबकि 1 सैटीमीटर से बड़े टुकड़ों की संख्या 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। यह मलबा पुराने उपग्रहों के अवशेष, रॉकेट के टूटे हिस्से और टकराव से उत्पन्न कणों का मिश्रण है। इनकी रफ्तार लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो किसी भी सक्रिय उपग्रह के लिए बेहद खतरनाक है। इतनी तेज गति से चलने वाला एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी सैटेलाइट को पूरी तरह नष्ट कर सकता है।

भारत के चंद्र मिशन भी इस खतरे से अछूते नहीं हैं। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को 2025 में कई बार अपनी कक्षा बदलनी पड़ी। अकेले इस मिशन के लिए 16 बार ऑर्बिट मैनुवर किए गए, ताकि संभावित टकराव से बचा जा सके। यह दशार्ता है कि अब अंतरिक्ष में काम करना पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और जोखिम भरा हो गया है। हर मिशन को न केवल अपने वैज्ञानिक उद्देश्यों पर ध्यान देना होता है, बल्कि उसे सुरक्षित बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। अंतरिक्ष में बढ़ती भीड़ का एक और असर लॉन्चिंग प्रक्रियाओं पर भी पड़ा है। कई बार रॉकेट लॉन्च को अंतिम क्षणों में टालना पड़ता है ताकि वह मलबे के रास्ते से बच सके। एक मामले में भारत को अपने एक मिशन की लॉन्चिंग 41 सेकंड तक टालनी पड़ी, ताकि संभावित टकराव से बचा जा सके। यह छोटी सी देरी दिखने में मामूली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे अत्यंत जटिल

गणनाएं और सुरक्षा उपाय होते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत ने हानेन्रह परि योजना की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य अंतरिक्ष में मौजूद मलबे और अन्य वस्तुओं की निगरानी करना है। इसके तहत उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जो 10 सैटीमीटर तक के मलबे को भी पहचान सके। यह प्रणाली भविष्य में सैटेलाइट्स को समय रहते खतरे से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दुनिया के अन्य देश भी इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका उन्नत कोलिजन अवॉइडेंस सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है और 2030 तक सक्रिय मलबा हटाने वाली तकनीकों को तैनात करने की योजना बना रहा है। चीन ने विशाल ग्राउंड-बेसड टेलीस्कोप सिस्टम तैयार किया है, जो अंतरिक्ष में मौजूद वस्तुओं की निगरानी करता है और उपग्रहों को सुरक्षित कक्षा में स्थानांतरित करने में मदद करता है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मलबे को हटाने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है, जिनमें छोटे कणों को जलाकर नष्ट करना या उनकी दिशा बदलना शामिल है।

अंतरिक्ष में मलबे की समस्या केवल तकनीकी नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भी मांग करती है। जैसे-जैसे अधिक देश और निजी कंपनियां अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही हैं, यह जरूरी हो गया है कि सभी एक साझा नियम और जिम्मेदारी के तहत काम करें। अगर इस दिशा में समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में अंतरिक्ष अभियानों की लागत और जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं। स्पेस डेब्रिस का बढ़ता खतरा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अंतरिक्ष अब केवल खोज और विकास का



क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो गई है। आने वाले वर्षों में सैटेलाइट्स की संख्या और बढ़ेगी, जिससे यह चुनौती और गंभीर हो सकती है। ऐसे में वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वे नई तकनीकों और रणनीतियों के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालें।

अंततः यह कहा जा सकता है कि अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा मानवता के लिए एक चेतावनी है। यदि हम समय रहते सतर्क नहीं हुए, तो यह हमारी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सैटेलाइट की सुरक्षा अब केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी बन चुकी है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता: सुविधा का वरदान या मूल्यों का संकट



समझ ही नहीं पाता कि जो वह देख रहा है या सुन रहा है वह सत्य है या निर्मित भ्रम, तब उसकी निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। यह स्थिति लोकार्थिक संस्थाओं के प्रति विश्वास को कमजोर करती है। आज सोशल माध्यमों पर ऐसी अनेक घटनाएँ सामने आती हैं, जहाँ किसी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जैसे बड़े नेताओं के साथ दिखाया जाता है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता। यह केवल व्यक्तिगत भ्रम नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर विश्वास की संरचना को कमजोर करने वाला प्रवाह है। जब झूठ और सत्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तब समाज में संशय, अविश्वास और अस्थिरता का वातावरण बनता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक और चिंताजनक पक्ष है साइबर अपराधों में इसका बढ़ता उपयोग। आज अपराधी किसी व्यक्ति की आवाज को नकल करके उसके परिचितों को धोखा देने में सक्षम हो गए हैं। परिवार के सदस्य या अधिकारी बनकर धन की ठगी करना अब अत्यंत सरल हो गया है। इस प्रकार की घटनाओं ने अनेक लोगों की जीवन भर की कमाई को पत्त भर में समाप्त कर दिया है। यह केवल आर्थिक क्षति नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा की भावना पर गहरा आघात है। वित्तीय क्षेत्र में भी इस तकनीक का दुरुपयोग गंभीर संकट उत्पन्न कर सकता है। स्वचालित हमलों के माध्यम से बैंकिंग

व्यवस्था की कमजोरियों का लाभ उठाया जा सकता है। यदि इस प्रकार के हमले व्यापक स्तर पर होते हैं, तो यह केवल व्यक्तिगत हानि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर कर सकते हैं। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब नियामक संस्थाएँ इन जटिल तकनीकों की गति और स्वरूप को समझने में पीछे रह जाती हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह तकनीक पूरी तरह निर्दोष नहीं है। विशाल आंकड़ा केंद्रों की स्थापना, ऊर्जा की अत्यधिक खपत, तथा खनिज संसाधनों का दोहन-ये सभी प्रकृति पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। कोबाल्ट और लिथियम जैसे खनिजों की बढ़ती मांग पर्यावरणीय असंतुलन और मानवीय शोषण दोनों को जन्म देती है। इस प्रकार यह तकनीक केवल सामाजिक या नैतिक ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चुनौती भी बन रही है। इन सभी चिंताओं के बीच यह समझना आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नकारा नहीं जा सकता। यह आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है और चिकित्सा, शिक्षा, अपदा प्रबंधन तथा उत्पादन के क्षेत्र में इसके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के स्वरूप में है। यदि इसे मानवीय मूल्यों, नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाए, तो यह एक वरदान

सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि इसके विकास और उपयोग के लिए स्पष्ट और सशक्त नियम बनाए जाएं। सरकारों और संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तकनीक का उपयोग पारदर्शी, सुरक्षित और उत्तरदायी तरीके से हो। कंपनियों को अपने तंत्र में ऐसी व्यवस्थाएँ विकसित करनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रमक सामग्री की पहचान और नियंत्रण संभव हो सके। साथ ही नागरिकों की जागरूकता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता के बिना कोई भी समाज इस चुनौती का सामना नहीं कर सकता। लोगों को यह समझना होगा कि जो कुछ वे देख या सुन रहे हैं, वह हमेशा सत्य नहीं हो सकता। सत्यापन की प्रवृत्ति को विकसित करना समय की आवश्यकता है। नैतिकता के स्तर पर यह भी आवश्यक है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले आंकड़े निष्पक्ष और उच्च गुणवत्ता वाले हों। यदि आधार ही पक्षपाती होगा, तो परिणाम भी पक्षपाती होंगे। इससे सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है। इसलिए निष्पक्षता, पारदर्शिता, गोपनीयता और उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों को इसके विकास का आधार बनाया जाए।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तकनीकी विकास हमारी परंपराओं और मूल्यों के साथ संतुलन बनाए रखे। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का डिजिटलीकरण और संरक्षण इस दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, किंतु यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग सम्मानपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ किया जाए। साररूप में यह कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक शक्तिशाली साधन है, जो मानव जीवन को नई दिशा दे सकता है। किंतु यदि इसे नैतिकता से अलग कर दिया जाए, तो यह उसी गति से विनाश का कारण भी बन सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम मूल्यों के विकास के साथ-साथ अपने नैतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करें। विज्ञान और मानवीय संवेदना के बीच संतुलन ही वह मार्ग है, जो हमें सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकता है।

धधकती धरती: विकास की दौड़ या विनाश की ओर?



योगेश कुमार गौयल
प्रकृति पिछले कुछ समय से बार-बार मयानक आध्यात्मिक के रूप में यह गंभीर संकेत देती रही है कि विकास के नाम पर हम प्रकृति से मयानक तरीके से जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप मौसम का मिजाज कब कहां किस कदर बदल जाए, कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता जा रहा है।

न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी तथा मौसम का निरन्तर बिगड़ता मिजाज गंभीर चिंता का सबब बना है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विगत वर्षों में दुनियाभर में दोहा, कोपेनहेगन, कानकुन इत्यादि बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद इस दिशा में अभी तक ठोस कदम उठते नहीं देखे गए हैं। दरअसल वास्तविकता यही है कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रकृति के बिगड़ते मिजाज को लेकर चर्चाएं और चिंताएं तो बहुत होती हैं, तरह-तरह के संकल्प भी दोहराये जाते हैं किन्तु सुख-संसाधनों की अंधी चाहत, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के दबाव के चलते इस तरह की चर्चाएं और चिंताएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदान करने तथा पृथ्वी को बचाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को 'विश्व पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है।

प्रकृति पिछले कुछ समय से बार-बार भयानक आधियों, तूफान और ओलावृष्टि के रूप में यह गंभीर संकेत देती रही है कि विकास के नाम पर हम प्रकृति से भयानक तरीके से जिस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप मौसम का मिजाज कब कहां किस कदर बदल जाए, कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विगत वर्षों में दुनियाभर में दोहा, कोपेनहेगन, कानकुन इत्यादि बड़े-बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद इस दिशा में अभी तक ठोस कदम उठते नहीं देखे गए हैं। दरअसल वास्तविकता यही है कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रकृति के बिगड़ते मिजाज को लेकर चर्चाएं और चिंताएं तो बहुत होती हैं, तरह-तरह के संकल्प भी दोहराये जाते हैं किन्तु सुख-संसाधनों की अंधी चाहत, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के दबाव के चलते इस तरह की चर्चाएं और चिंताएं अर्थहीन होकर रह जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों में जागरूकता पैदान करने तथा पृथ्वी को बचाने के लिए प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को 'विश्व पृथ्वी दिवस' मनाया जाता है।

सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखाकर हमें चेतावनी भी देती रही है किन्तु जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर वैश्विक चिंता व्यक्त करने से आगे हम शायद कुछ करना ही नहीं चाहते। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सीजने से प्रकाशित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त संसार' के अनुसार हम यह समझना ही नहीं चाहते कि पहाड़ों का सीना चौरकर हरे-भरे जंगलों को तबाह कर हम जो कंक्रीट के जंगल विकसित कर रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर हम अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। पहाड़ों में बढ़ती गर्माहट के चलते हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें सुनने की मिलती रहती हैं। पहाड़ों की इसी गर्माहट का सीधा असर निचले मैदानी इलाकों पर पड़ता है, जहां का पारा अब हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। धरती का तापमान यदि इसी प्रकार साल दर साल बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में हमें इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा क्योंकि हमें यह बखूबी समझ लेना होगा

कि जो प्रकृति हमें उपहार स्वरूप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी तथा दूरों जनोंपयोगी चीजें दे रही है, अगर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पैदा किए जा रहे पर्यावरण संकट के चलते प्रकृति कुपित होती है तो उसे सब कुछ नष्ट कर डालने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी। करीब दो दशक पहले देश के कई राज्यों में जहां अप्रैल माह में अधिकतम तापमान औसतन 32-33 डिग्री रहता था, अब वह 40 के पार रहने लगा है। मौसम विभाग का तो अनुमान है कि अगले तीन दशकों में इन राज्यों में तापमान में वृद्धि 5 डिग्री तक दर्ज की जा सकती है और इसी प्रकार तापमान बढ़ता रहा तो एक ओर जहां जंगलों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी, वहीं धरती का करीब 20-30 प्रतिशत हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाएगा तथा एक चौथाई हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा, जिसके दायरे में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण आस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप इत्यादि आएंगे। सवाल यह है कि धरती का तापमान बढ़ते जाने के प्रमुख कारण क्या हैं? हृदयप्रदूषण मुक्त सांसें पुस्तक के मुताबिक

इसका सबसे अहम कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो तमाम तरह की सुख-सुविधाएं व संसाधन जुटाने के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों की ही देन है। पेट्रोल, डीजल से उत्पन्न होने वाले धुएँ व वातावरण में कार्बन डाईऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वातावरण में पहले की अपेक्षा 30 फीसदी ज्यादा कार्बन डाईऑक्साइड मौजूद है, जिसकी मौसम का मिजाज बिगाड़ने में अहम भूमिका है। पेड़-पौधे कार्बन डाईऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में वन-क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर कंक्रीट के जंगलों में तब्दील किया जाता रहा है। एक ओर अहम कारण है बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि जहां 20वीं सदी में वैश्विक जनसंख्या करीब 1.7 अरब थी, अब बढ़कर 8 अरब से भी ज्यादा हो चुकी है। बहरहाल, अगर प्रकृति से खिलवाड़ कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर हम स्वयं इन समस्याओं का कारण बने हैं और हम चाकई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर चिंतित हैं तो इन समस्याओं का निवारण भी हमें ही करना होगा ताकि हम प्रकृति के प्रकोप का भाजन होने से बच सकें अन्यथा प्रकृति से जिस बड़े पैमाने पर खिलवाड़ हो रहा है, उसका खामियाजा समस्त मानव जाति को अपने विनाश से चुकाना पड़ेगा।



क्या आप भी जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं? ये हैं फायदे एवं नुकसान

एक तो लोगों को नौकरी मिलना आज के समय में बेहद मुश्किल का कार्य है, वहीं कई लोग भाग्यशाली होते हैं, जिन्हें एक नौकरी छोड़ने से पहले ही दूसरी नौकरी मिल जाए। ऐसे में थोड़ी ग़ोथ के लिए लोग बाग जल्दी-जल्दी नौकरी चेंज करने लगते हैं। शायद आप भी उनमें से हों, किन्तु अगर आप भी जल्दी जल्दी नौकरी चेंज करते हैं तो यह जान लें कि शार्ट टर्म में बेशक इसके कुछ फायदे दिखें, किन्तु दीर्घावधि में इसका काफी नुकसान होता है।

हालांकि अभी के समय में हालात यह हैं कि अब पहले की तरह लोग एक ही नौकरी पर बहुत दिन तक कार्य नहीं करते हैं, बल्कि नौकरी चेंज करने में वह अपनी ग़ोथ देखते हैं, और उसी अनुरूप डिस्मिशन भी लेते हैं। किन्तु जॉब बदलने का फेराला कुछ मामलों में बेशक ठीक लगता है, किन्तु कुछ मामलों में यह कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आइये जानते हैं, अगर फायदे की बात करें तो आप यह जान लीजिए कि जॉब बदलने में सबसे पहले तो कुछ परसेंट ही सही, मगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है। निश्चित रूप से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे उसके काम के अधिक से अधिक पैसे मिलें, और एक नौकरी में अगर उस अनुरूप ग़ोथ नहीं होती है, तो वह जॉब बदलना चाहता है, और ऐसे में उसे तुरंत ही ग़ोथ मिल जाती है।

वहीं अगर दूसरे फायदे की बात करें तो इससे पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका नेटवर्क बेहतर होता है। अगर एक कंपनी में आप जॉब करते हैं, फिर दूसरी कंपनी में जाते हैं, और इस तरीके से अलग-अलग कंपनियों में आपका बेस तैयार होता चला जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही कंपनी में काम करने पर आप कंफर्ट ज़ोन में आ जाते हैं। आपकी रिस्कल कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जाती है, तो दूसरी कंपनी में जब आप जाते हैं, तो वहां कुछ ना कुछ नया सीखने को अवश्य मिलता है। चाहे वहां आपका नया सीनियर हो, चाहे वहां का इनवायरमेंट हो, आप उस कंपनी से नई चीजें जरूर सीखते हैं, और यह वह चीज है जो आपको आने वाले दिनों में मजबूती करती है। इसके अलावा कई भारत लोग एक जगह पर कार्य करने से बोर भी हो जाते हैं, ऐसे में नयी जॉब में उन्हें नयापन भी मिलता है।

हालांकि यह इसका पॉजिटिव पक्ष है, किन्तु कुछ निगेटिव पक्ष भी हैं, जिन्हें आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। नुकसान की बात करें तो बार बार जॉब चेंज करने से पोजीशन के मामले में आपके आगे बढ़ने पर

असर पड़ सकता है। जी हाँ! एक ही कंपनी में जब आप काम करते हैं, तो वहां आपकी कंस्टेंट ग़ोथ होती है। वहां आपको प्रमोशन मिलता रहता है, किन्तु जब आप दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो सीनियर पोजीशन पर आपको पहुंचने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। इससे आपकी लॉयल्टी भी चेक की जाती है। अगर आप कुछ ज्यादा ही जॉब चेंज करते हैं, तब आपकी किसी हायर पोजीशन पर जॉब देने से एचआर मैनेजर निश्चित ही कई बार सोचेगा। कंपनी अगर किसी जिम्मेदारी वाली पोस्ट पर आपकी हायरिग कर भी लेती है, तो भी कंपनी श्योर नहीं हो पाती है कि आप आखिर कितने दिन जॉब करेंगे? कहीं आप बीच में ही जॉब छोड़ कर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे? ऐसे में आप शक के घेरे में आ जाते हैं!

यह कार्य सिर्फ पोजीशन के मामले में ही नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट अलॉटमेंट के मामले में भी है, तो वलाइंट इंटरवेंशन के मामले में भी है। जब तक आप किसी कंपनी के लम्बे समय तक वाफादार नहीं होते हैं, तब तक किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमांड आपके हाथ में देने से निश्चित रूप से वह कंपनी हिचकियाएगी। इसी प्रकार से बड़े वलाइंट हैडलिंग में भी कंपनी आपको तब तक इवॉल्व नहीं करेगी, जब तक आप उसके प्रति लॉयल साबित न हो जाएं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी संभावनाओं से आपके दूर रहने की शुरुआत हो जाती है।

कंपनी बार-बार चेंज करने का आपके फाइनेंसियल पोजीशन पर भी ख़ासा असर पड़ता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करें, चाहे आप होम लोन या दूसरे लोन के लिए अप्लाई करें, आपकी फाइनेंसियल स्टेटिलिटी जरूर चेक की जाती है। अगर किस कंपनी में कितने लंबे समय तक रहे हैं, यह आपके लिए एक प्लस प्वाइंट साबित होता है। वहीं अगर आप बार-बार अपनी जॉब चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंसियल स्टेटिलिटी पर एक सवाल खड़ा होता है।

मैनेजरियल स्किल डेवलपमेंट पर पड़ता है फर्क

जी हाँ! ऊपर से आपको बेशक लगे कि आप कुछ चीजें ऊपर ऊपर समझ गए हैं, किन्तु प्रबंधन के गुणों को आप तब तक नहीं समझ सकते, जब तक आप किसी कंपनी में देर तक नहीं टिकेंगे! कहीं टिक कर काम करने के बाद ही कंपनी पॉलिटिक्स, प्रबंधन टेक्निक आप समझ पाते हैं। कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिस्मिशन किस प्रकार लेती है, वास्तव में उसकी रुचि और भविष्य की योजनायें क्या हैं, यह आप गहराई से एक समय के बाद ही समझ पाते हैं। अगर बाद में आप कभी अपना उद्यम शुरू करना चाहें, तो इसलिए जरूरी है कि किसी कंपनी में आप देर तक टिक कर काम करें, अन्यथा आप उसकी गहराई को नहीं समझ पाएंगे।



विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलिमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं।

मौजूदा तकनीकी दौर में पॉलिमर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इनमें प्लास्टिक, मोल्डेड सामग्री, सिंथेटिक फाइबर, रबर आदि शामिल हैं। ईको-फ्रेंडली और रीसाइक्लेबल प्लास्टिक के साथ इन सभी पॉलिमर प्रोडक्ट्स के उचित प्रबंधन की आवश्यकता भी समय के साथ बढ़ रही है। यह काम पॉलिमर इंजीनियर्स करते हैं। वे प्लांट डिजाइन, प्रोसेस डिजाइन और थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। विदेश ही नहीं, भारत में भी कई पॉलिमर और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं। नतीजतन, करियर विकल्प के रूप में केमिकल इंजीनियरिंग या पॉलिमर इंजीनियरिंग का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं के बाद पॉलिमर साइंस में बीटेक कर सकते हैं। आज के इस लेख में हम आपको पॉलिमर साइंस में बीटेक के बाद करियर अवसर के बारे में जानकारी देंगे-

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के अवसर

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद आप सरकारी फर्मों जैसे सेंट्रल ग्लास एंड

पॉलिमर साइंस में बीटेक करने के बाद है शानदार करियर संभावनाएं

सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राउरकेला और सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि में बतौर जूनियर रिसर्च फेलो काम कर सकते हैं। इन फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर कम से कम 55% अंकों के साथ एम टेक डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई भी नेट के लिए बैठ सकता है। जिन उम्मीदवारों ने अपनी बी टेक डिग्री में 60% अंक प्राप्त किए हैं, वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वैज्ञानिक या इंजीनियर के रूप में 40,000/- रुपये के मासिक वेतन के साथ काम कर सकते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी वैज्ञानिक बी पद की भूमिका में पॉलिमर इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती करता है। इनके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड (बीसीपीएल) जैसे संगठन भी पॉलिमर इंजीनियरिंग में बी टेक स्नातकों को नियुक्त करते हैं। इनके अलावा स्नातक डिग्री धारक पेट्रोप्लियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑयल इंडिया लेबोरेटरीज, पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग प्लांट्स और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन (ओएनजीसी) आदि विभागों में

भी रोजगार पा सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में लेक्चरर पद का विकल्प भी चुन सकते हैं।

पॉलिमर इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद निजी क्षेत्र के अवसर

जर्मन आधारित कंपनी विंडमोलर एंड होल्शर, अक्सर अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुभाग में संचालन करने के लिए पॉलिमर इंजीनियरों की भर्ती करती है। 17 से 8 साल के कार्य अनुभव वाले लोग एलाइड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स/बिजनेस डेवलपमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आप 35,000/- से रु 150,000/- प्रति माह तक की सैलरी पा सकते हैं। अपोलो टायर्स लिमिटेड, सिप्ट लिमिटेड आदि जैसी टायर कंपनियों को भी पॉलिमर इंजीनियर्स की जरूरत है। पॉलिमर इंजीनियरिंग में स्नातकों के लिए क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर्स/टेक्नोलॉजिस्ट, पॉलिमर स्पेशलिस्ट आदि सामान्य जॉब प्रोफाइल हैं।



प्रतिभावान विद्यार्थियों को तराशती योजना राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

स्कॉलरशिप

परीक्षा आयोजन के आधार पर कक्षा 8 की परीक्षाओं के लिए बड़े छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए 1000 स्कॉलरशिप दी जाती है। स्कॉलरशिप की राशि प्रत्येक माह 500 रूपए होती है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 7.5 प्रतिशत और विकलांग छात्रों के लिए 3 प्रतिशत स्कॉलरशिप आरक्षित होती है। स्कॉलरशिप का भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता को न देकर संबद्ध संस्थान के प्रमुख के माध्यम से दिया जाता है।

चयन प्रक्रिया

प्रतिभाओं की पहचान दो स्तरीय लिखित परीक्षा के आधार पर की जाती है। प्रथम स्तर का चयन अलग-अलग राज्य/यूनियन टेरिटरीज द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। प्रथम स्तर की परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही एनसीईआरटी द्वारा संचालित द्वितीय स्तर की परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र माने जाते हैं। राज्य और यूनियन टेरिटरीज राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना की प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा के साथ राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना की भी परीक्षा आयोजित करते हैं।

पात्रता

मान्यताप्राप्त विद्यालयों के 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी उस राज्य/यूनियन टेरिटरीज द्वारा संचालित प्रथम स्तर की परीक्षा में बैठने के पात्र होते हैं, जिस राज्य में विद्यालय स्थित है।

आवेदन प्रपत्र

आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने के लिये राज्य संपर्क अधिकारी से संपर्क करें। आवेदन-प्रपत्र एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन प्रपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए। आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि तथा प्रपत्र कहां जमा कराया जायेगा, इस संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र के संपर्क अधिकारी से पता किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों की आवेदन प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां भिन्न हो सकती हैं।

शुल्क

एनसीईआरटी द्वारा द्वितीय स्तर की परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। राज्य और यूनियन टेरिटरीज प्रथम परीक्षा के लिए अपेक्षित शुल्क के भुगतान के लिए अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इन्होंने आवेदन प्रपत्र जमा करने से पहले कितनी और कैसे फीस दी जायेगी, इसका पता अपने राज्य संपर्क अधिकारी से लगा लेना चाहिए।

परीक्षा माध्यम

परीक्षा हिन्दी व अंग्रेजी के साथ असमी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू में संचालित की जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र में जिस भाषा में परीक्षा देना चाहते हैं, उस विकल्प का उल्लेख करें। इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को उस भाषा में प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी।

परीक्षा-विधि

8वीं के लिए लिखित परीक्षा की विधि इस प्रकार है- प्रथम स्तर की राज्य/यूनियन टेरिटरी स्तर पर संचालित परीक्षा में दो भाग होंगे (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी)। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। द्वितीय स्तर की राष्ट्रीय स्तर पर संचालित परीक्षा में (अ) मानसिक योग्यता परीक्षण (एमएटी) और (ब) शैक्षिक योग्यता परीक्षण (एसएटी) शामिल होंगे। इनमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित विषय शामिल होंगे। (स) इंटरव्यू - इंटरव्यू के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर संचालित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा में प्रथम भाग एमएटी और द्वितीय भाग एसएटी शामिल होंगे। दोनों परीक्षाएं एक छठे से अंतराल पर अलग-अलग ली जाएंगी। मानसिक योग्यता परीक्षा-एमएटी। चार विकल्पों सहित इसमें

नेशनल टेलेंट सर्च यानी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एनसीईआरटी की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना और उनकी प्रतिभा को बढ़ाना है। इसके तहत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन और विधि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह योजना प्रतिभावान विद्यार्थियों को मासिक स्कॉलरशिप के रूप में आर्थिक मदद दे कर सहयोग देती है। इस योजना में बसिक साइंस, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य के पाठ्यक्रमों के लिए पीएचडी स्तर तक सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन एवं विधि के लिए पीजी स्तर तक सहायता दी जाती है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कक्षा 8 स्तर पर किया जाता है।

90 मल्टीचॉइस प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। समय 90 मिनट होगा।

स्कॉलरशिप पाने की सामान्य शर्तें

स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार अनुसूचित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों। वह अच्छे आचरण बनाए रखता हो (संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित) और अपना अध्ययन एक नियमित विद्यार्थी के रूप में कर रहा हो। बिना उचित अवकाश के अनुपस्थित न होता हो। पूर्णकालिक आधार पर अध्ययन करता हो। कोई रोजगार नहीं करता हो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना पीएचडी कोर्स को छोड़ कर छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं को कोई अन्य स्कॉलरशिप स्वीकार करने से वंचित नहीं करती, अलबत्ता किसी भी पाठ्यक्रम के लिए विदेश में अध्ययन के लिए कोई स्कॉलरशिप उपलब्ध नहीं होगी। यदि कोई प्राप्तकर्ता पंजीकरण/प्रवेश के एक माह के अंदर अपने पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ता है तो उसे कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी।



विजुअल मर्चेन्डाइजिंग के क्षेत्र में हैं अपार संभावनाएं

विजुअल मर्चेन्डाइजिंग शब्द भले ही कुछ लोगों के लिए नया हो, लेकिन सेल्स और एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोग इससे गली-भांति वाकिफ हैं। विजुअल मर्चेन्डाइजिंग वास्तव में एक आर्ट है, जिसमें एक व्यक्ति किसी प्रॉडक्ट या सर्विस को वलाइंट्स के सामने कुछ इस तरह पेश करता है ताकि वह सेल्स को बढ़ावा दे सके। अब इस कॉन्सेप्ट को रिटेल सेक्टर में एक मार्केटिंग टूल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में वह सभी गतिविधियां शामिल हैं, जो रिटेल स्टोर्स में उत्पादों की बिक्री बढ़ाने में मदद करती हैं। उदाहरण के तौर पर, प्रॉडक्ट के संभावित ग्राहकों के माइंड को समझना और उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में शिथिल करना व प्रॉडक्ट को बेहद इफेक्ट व क्रिएटिव तरीके से पेश करना आदि। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस करियर के बारे में

जगहों पर विजुअल मर्चेन्डाइजिंग को फेशन डिजाइनिंग या फेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के तहत पढ़ाया जाता है। कॉरियर एक्सपर्ट के अनुसार, विजुअल मर्चेन्डाइजिंग के कोर्स में छात्रों को विजुअल मर्चेन्डाइजिंग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है जैसे कि रिटेल स्टोर का लेआउट और डिजाइन, इंटीरियर डेकोरेशन, स्टोर के अंदर फर्नीचर और फिक्स्चर की स्थापना, स्टोर डिस्प्ले और उत्पादों की प्रस्तुति, विभिन्न संचार साधनों के उपयोग के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करना।

व्यक्तिगत गुण

इस क्षेत्र में कॉरियर देख रहे छात्रों में डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के गुण का होना बेहद आवश्यक है। एक विजुअल मर्चेन्डाइजर में बेहतरीन ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होने के साथ-साथ प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व टाइम मैनेजमेंट आदि विशेषताएं भी होनी चाहिए। इसके अलावा उनमें संचार व इंटरपर्सनल स्किल्स, समस्या सुलझाने की क्षमता और कंप्यूटर का ज्ञान होना भी जरूरी है। कॉरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि विजुअल मर्चेन्डाइजर को उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को जानना आना चाहिए और उसे रुझानों का भी पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए।

संभावनाएं

शॉपिंग मॉल, फाइव स्टार होटल, बुटीक व रिटेल आउटलेट्स की संख्या बढ़ने के साथ ही विजुअल मर्चेन्डाइजर्स की मांग में भी काफी इजाजा हुआ है। विजुअल मर्चेन्डाइजर फेशन बुटीक, शॉपिंग मॉल, एम्पोरिया, डिजाइन कंपनी, आर्टिटेक्चर फर्म, थीम पार्टी ऑर्गेनाइजिंग कंपनी आदि में जॉब कर सकते हैं। वे प्रदर्शनियों, मेलों, ब्यूटी कॉन्टैक्ट, अवाइं सेरेमनी, मॉल, रिटेल में विंडो डिस्प्ले के लिए अनुबंध के आधार पर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में एक फ्रेशर भी दस से पंद्रह हजार आसानी से कमा सकता है। वहीं कुछ समय के अनुभव के बाद आप किसी बड़े ब्रांड के रिटेल आउटलेट में काम कर सकते हैं और एक आकर्षक पैकेज पा सकते हैं।

क्या है विजुअल मर्चेन्डाइजिंग

एजुकेशन एक्सपर्ट बताते हैं कि विजुअल मर्चेन्डाइजिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विजुअल मर्चेन्डाइजर कहा जाता है। विजुअल मर्चेन्डाइजर ऐसे पेशेवर हैं जो किसी भी ब्रांड, एक चेहरे को देने के लिए जिम्मेदार हैं। वे ऑनलाइन शॉपिंग और रिटेल स्टोर दोनों के लिए विंडो और स्टोर डिस्प्ले में अवधारणा, डिजाइन और कार्यान्वयन करते हैं। वे स्टोर थीम की योजना बनाते हैं, डिस्प्ले के लिए प्रॉपर की व्यवस्था करते हैं, डिस्प्ले फिक्स्चर और लाइटिंग की व्यवस्था करते हैं, ओपनिंग से पहले स्टोर सेट करते हैं, फ्लोर प्लान के साथ काम करते हैं और डिस्प्ले को बनाने के लिए सेल्स पलोर पर स्टोर कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। एक विजुअल मर्चेन्डाइजर का मुख्य उद्देश्य स्टोर की छवि के अनुरूप डिस्प्ले बनाना और अधिक ग्राहकों को स्टोर में लाना है।

शैक्षणिक योग्यता

आजकल ऐसे कई इंस्टीट्यूट हैं जो विजुअल मर्चेन्डाइजिंग से संबंधित सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स कराते हैं। इस कोर्स को करने के लिए छात्र का 12वीं पास होना आवश्यक है। हालांकि अधिकतर

प्रमुख संस्थान

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बेंगलूर
- द सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई
- स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज, कोच्चि
- बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, गोंडार एण्ड



मारुति सुजुकी का 2 लाख प्रतीक्षा कारों की आपूर्ति पर जोर

- खरखोदा व गुजरात संयंत्रों में 5 लाख यूनिट तक क्षमता बढ़ेगी

नई दिल्ली ।

देश की अग्रणी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी 2 लाख से अधिक कारों की लंबी प्रतीक्षा सूची से निपटने के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि कर रही है। कंपनी के एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि अगले कुछ महीनों में यह आपूर्ति पूरी करने का लक्ष्य है, जिसके लिए उत्पादन में बढ़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है, जिसमें छोटी कारों पर विशेष ध्यान रहेगा। मारुति सुजुकी के अधिकारी ने जानकारी दी कि कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 2026-27 के अंत तक 5 लाख अतिरिक्त यूनिट्स तक बढ़ाएगी। इसमें हरियाणा के खरखोदा और गुजरात संयंत्रों में प्रत्येक की क्षमता में 2.50 लाख कारों की वृद्धि शामिल होगी। इन कारखानों की असेंबली लाइनें मॉडल बदलने में सक्षम होंगी, जिससे प्रतीक्षा सूची वाली छोटी कारों की बड़ी मांग को पूरा किया जा सकेगा। वर्तमान में, डीलरों के पास केवल एक सप्ताह की जरूरत भर का स्टॉक है, जबकि सामान्य तौर पर यह 30 दिन का होता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की योजना के बारे में उन्होंने बताया कि सेल आयात के कारण कुल आयातित पुर्जे 50 फीसदी से अधिक होने के कारण मारुति फिलहाल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहनयोजना के लाभ के लिए पात्र नहीं है। इस चुनौती से निपटने के लिए, कंपनी देश में बैटरियों को पैकेज करने की योजना बना रही है, जिससे आयातित सामग्री कम होगी और पीएलआई पात्रता मिल सकेगी। कंपनी ने हाल ही में निर्यात के बाद ई-विटारा को घरेलू बाजार में उतारा है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी के छोटी कारों पर माल एवं सेवा कर कम करने के फैसले से इस सेगमेंट को जबरदस्त बढ़ावा मिला है, और वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की कुल बिक्री का 70 फीसदी हिस्सा इन्हीं छोटी कारों का था, जिससे सरकारी राजस्व पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिका-ईरान युद्ध के संभावित प्रभावों पर, उन्होंने कच्चे तेल, जैसे स्टील, की कीमतों में वृद्धि और कार निर्माण की लागत में इजाफे की आशंका जताई, जिससे लाभप्रदता पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा, हालांकि उन्होंने मांग में निरंतर वृद्धि की उम्मीद जताई।

एफपीआई की रिकॉर्ड बिकवाली, भारतीय बाजार से 1.68 लाख करोड़ निकाले

- ईरान युद्ध से उपजे तेल संकट ने 1.1 लाख करोड़ के शेयर बेचने पर मजबूर किया

नई दिल्ली ।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने 2026 में भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपये की निकासी की है, जो पिछले पूरे साल की कुल बिकवाली से भी अधिक है। ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न हुए भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने विदेशी निवेशकों को जोखिम भरी संपत्तियों से दूर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप अकेले मार्च में 1.1 लाख करोड़ रुपये की बड़ी बिकवाली हुई। यह बिकवाली फरवरी के आशावाद के ठीक उलट है, जब भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौते और अमेरिकी शुल्क में कमी की उम्मीदों पर एफपीआई शूढ़ खरीदार बने थे। हालांकि, अमेरिका-ईरान युद्ध, जिसमें ईरान ने खाड़ी देशों में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला किया और होमरुज स्ट्रेट को अवरुद्ध कर दिया, ने निवेशकों का विश्वास हिला दिया। होमरुज स्ट्रेट वैश्विक तेल और गैस शिपमेंट का लगभग 20% संभालता है, जिसके चलते ब्रेट क्रूड की कीमतें 22 फीसदी बढ़कर 90.1 प्रति बैरल हो गई हैं। भारत के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि देश अपनी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। तेल की बढ़ती कीमतें राजकोषीय घाटे को बढ़ाती हैं, महंगाई को बढ़ावा देती हैं और आर्थिक विकास पर नकारात्मक असर डालती हैं। एफपीआई की यह बिकवाली केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अधिकांश उभरते बाजारों में देखी गई है, हालांकि दक्षिण कोरियाई बाजार को छोड़कर भारत में निकासी अन्य उभरते बाजारों से अधिक रही है।

डॉलर की मजबूती से सोना फिसला, चांदी भी हुई सस्ती

- सोना 153,736 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 250,925 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली ।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर मंगलवार के कारोबार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर की मजबूती और निवेशकों द्वारा की गई मुनाफावृत्ती के चलते सोने की कीमतें गिरे हैं। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण कच्चे तेल की ऊँची कीमतें भी सोने पर दबाव डाल रही हैं। चांदी की कीमतों में भी नरमी देखी गई। सुबह 10:30 बजे के आसपास एमसीएक्स पर सोने का जून वायदा 207 रुपए गिरकर

153,736 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी की कीमतों में 250,925 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर था।

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार बढ़ते अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की ऊँची कीमतें सोने-चांदी को अस्थिर बनाए हुए हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का व्यापार डॉलर में होने से, इसकी बढ़ती कीमतें डॉलर की मांग बढ़ाती हैं, जिससे सोने पर दबाव आता है। ब्रेट क्रूड लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जो बाजार की चिंताओं को बढ़ा

शेयर बाजार में बढ़त के साथ व्लोजिंग; सेंसेक्स 753 अंक चढ़ा

निफ्टी 24550 के पारनिवेशकों को 3 लाख करोड़ का फायदा

मुंबई ।

पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के बीच मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों ने शानदार वापसी की और एक मजबूत बढ़त के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे विवाद में कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार के प्रमुख सूचकांकों को नई ऊर्जा दी। मंगलवार को शेयर बाजार निवेशकों को करीब 3 लाख

करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। शुरुआती कारोबार में धीमी चाल के बाद बाजार ने तेज रफ्तार पकड़ी। बीएसई सेंसेक्स 753.03 अंकों यानी 0.96 प्रतिशत की दमदार बढ़त के साथ 79,273.33 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स 211.75 अंक या 0.87 प्रतिशत चढ़कर 24,576.60 पर पहुंच गया। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से ट्रेड, हिंदुस्तान यूनिवर्सल, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और

एक्सिस बैंक प्रमुख विजेताओं में शामिल थे। अमेरिकी बाजारों में मजबूती और एशियाई बाजारों (निकेई और कोसमी) में बढ़त का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ा। पॉजिटिव ग्लोबल सेंटीमेंट्स ने निवेशकों का उत्साह बढ़ाया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्रेट क्रूड की कीमतों में कमी आई है। भारत तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए तेल सस्ता होने से इकोनॉमी और कंपनियों के मार्जिन को फायदा मिलता है। अमेरिका में 10 साल के ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। जब बॉन्ड यील्ड गिरती है,



तो विदेशी निवेशक (एफआईआई) भारतीय जैसे उभरते बाजारों में पैसा लगाना पसंद करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों में शुरुआती कारोबार में अच्छी खरीदारी देखी गई, जिससे इंडेक्स ऊपर चढ़ा।

ईंधन कीमतों में राहत, 21 अप्रैल को मी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

नई दिल्ली ।

कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय उपभोक्ताओं को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने 21 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे आम जनता को राहत है। देश के प्रमुख शहरों में मंगलवार को भी ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपये और डीजल 90.03 रुपये पर स्थिर है। कोलकाता में पेट्रोल 105.41 रुपये और डीजल 92.02 रुपये है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 101.23 रुपये और डीजल 92.81 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। बंगलुरु में पेट्रोल 102.92 रुपये और डीजल 90.99 रुपये, जबकि गुवागम में पेट्रोल 95.65 रुपये और डीजल 88.10 रुपये प्रति लीटर पर कायम हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें पहले तेजी से बढ़ी थीं, जिससे ब्रेट क्रूड लगभग 95 डॉलर और डब्ल्यूटीआई क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि अब बाजार में स्थिरता लौटने से घरेलू कीमतों पर फिलहाल दबाव नहीं दिख रहा है।



भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, 2027 तक 6.6 फीसदी वृद्धि का अनुमान संयुक्त राष्ट्र

घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र का अहम योगदान; हरित नौकरियों के सृजन में भी भारत की अहम भूमिका

नई दिल्ली ।

संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 6.4 प्रतिशत और 2027 तक 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग एशिया व प्रशांत (ईएससीएपी) द्वारा जारी इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2026 शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत की मजबूत घरेलू खपत और सेवा क्षेत्र को इस वृद्धि का मुख्य चालक बताया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में 2025 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत की वृद्धि दर 2025 में

बढ़कर 7.4 प्रतिशत तक पहुंच गई, जिसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मजबूत मांग, जीएसटी दरों में कटौती और अमेरिकी शुल्कों से पहले हुए निर्यात से समर्थन मिला। हालांकि, 2025 की दूसरी छमाही में अमेरिकी शुल्कों के कारण निर्यात में गिरावट से कुछ धीमी गति देखी गई, लेकिन सेवा वृद्धि का प्रमुख चालक बना रहा। देश में मुद्रास्फीति इस वर्ष 4.4 प्रतिशत और 2027 में 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद, विकासशील एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रवाह में कमी आई है। इस क्षेत्र में 2025 में एफडीआई दो प्रतिशत घटा, जबकि वैश्विक प्रवाह में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके

जेएनपीए एसईजेड में वेलस्पन वन और इंडेव इंफ्रा के बीच साझेदारी

मुंबई ।

वेयरहाउसिंग एवं औद्योगिक रियल एस्टेट मंच वेलस्पन वन ने जेएनपीए विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में इंडेव इंफ्रा को 2.10 लाख वर्ग फुट क्षेत्र का गोदाम पट्टे पर दिया है। यह कदम इंडेव इंफ्रा को अपनी फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन क्षमताओं को बढ़ाने और बंदरगाह से जुड़े लॉजिस्टिक्स संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करेगा। वेलस्पन वन ने कहा कि यह समझौता इंडेव इंफ्रा की बाजार में उपस्थिति को मजबूत करेगा, जिससे उसे निंबांध, बंदरगाह से जुड़े आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रवाह को समर्थन देने की क्षमता मिलेगी। इंडेव इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के एक अधिकारी ने कहा कि यह साझेदारी व्यापार प्रवाह को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और ग्राहकों को एकत्रीकृत एवं मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करने की हमारी क्षमता को मजबूत करती है।

विदेशी शेयरधारकों से भारतीय वित्तीय संस्थानों की साख मजबूत होगी फिच

- विकसित बाजारों का अनुभव रखने वाले अधिग्रहणकर्ता जोखिम नियंत्रण और निगरानी में लेा कते हैं धार

नई दिल्ली (ईएमएस)। फिच रेटिंग्स ने मंगलवार को कहा कि भारतीय वित्तीय संस्थानों में विदेशी शेयरधारकों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी उनके ऋण खंड (क्रेडिट प्रोफाइल) के लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार यह दीर्घकालिक पूंजी उपलब्धता, वित्तपोषण लचीलेपन और कुछ मामलों में कामकाज के मानकों में सुधार के माध्यम से संस्थानों की साख को मजबूत करेगा। फिच ने बताया कि हाल के समय में

विदेशी निवेशकों की बढ़ती रुचि भारत की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं, वित्तीय क्षेत्र के नियंत्रण तथा बेहतर जोखिम प्रबंधन ढांचे में उनके बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। एजेंसी का मानना है कि निवेशक ऐसे मंच की तलाश में हैं जिनमें विस्तार योग्य वितरण क्षमता और स्थानीय विशेषज्ञता हो। विकसित बाजारों का अनुभव रखने वाले अधिग्रहणकर्ता जोखिम नियंत्रण और निगरानी में सुधार ला सकते हैं, जबकि प्रतिष्ठित रणनीतिक शेयरधारक पूंजी की

लागत कम करने में सहायक होते हैं। लाफि, रेटिंग एजेंसी ने इस बात पर जोर दिया कि केवल विदेशी रुचि को मजबूत ऋण आधार का विश्वसनीय संकेत नहीं माना जा सकता। फिच के अनुसार, वे लेनदेन जो आंतरिक नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन और नेतृत्व की जवाबदेही को मजबूत करते हैं, केवल वित्तीय लाभ के लिए किए गए सौदों की तुलना में अधिक ऋण-संबंधी महत्व रखते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निवेश वित्तीय संस्थानों की



मूलभूत मजबूती को बढ़ाए। च का मानना है कि बैंकों की तुलना में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफआई) में विदेशी शेयरधारकों के नियंत्रण हासिल करने की संभावना अधिक है, क्योंकि नियमों के तहत एनबीएफआई में पूर्ण विदेशी स्वामित्व की अनुमति है।

पीपीएफ में निवेश कर सुरक्षित बचत के साथ पाएं शानदार रिटर्न और टैक्स छूट!

- 70,000 सालाना निवेश, मैच्योरिटी पर मिलेगा लगभग 18.98 लाख का बड़ा फंड

नई दिल्ली । वित्तीय सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए निवेश करना हर व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। ऐसे में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) एक ऐसी सरकारी योजना है जो न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखती है, बल्कि लंबी अवधि में इसे कई गुना बढ़ाने का शानदार अवसर भी प्रदान करती है। साथ ही, यह टैक्स बचाने का भी एक प्रभावी माध्यम है, जिससे निवेशक दोहरे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पीपीएफ भारत सरकार द्वारा समर्थित एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है, जिसमें जोखिम लगभग न के बराबर होता है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हुए एक अच्छा फंड तैयार करना चाहते हैं। इसमें आप सालाना न्यूनतम 500 से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, जिसे एकमुश्त या छोटे-छोटे मासिक/वार्षिक किस्तों में जमा किया जा सकता है। वर्तमान में इस योजना पर लगभग 7.1 फीसदी वार्षिक ब्याज दर मिल रही है, हालांकि यह दर सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाती है। इस योजना की मैच्योरिटी अवधि 15 साल होती है। अगर कोई निवेशक हर साल लगातार 70,000 रुपए जमा करता है, तो 15 साल में उसका

कुल निवेश 10.5 लाख रुपए होगा। 7.1 फीसदी की वर्तमान अनुमानित ब्याज दर के हिसाब से, उसे लगभग 8,48,498 रुपए का ब्याज मिलेगा। इस प्रकार, मैच्योरिटी पर कुल राशि लगभग 18,98,498 रुपए होगी, जो आपके मूल निवेश का दोगुने से भी ज्यादा है। पीपीएफ को टैक्स सेविंग के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। इसके अलावा, इस योजना में मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट, दोनों ही पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं। आप अपना पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आसानी से खोल सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है। अन्य सुविधाओं में 3 से 6 साल के बीच लोन लेने की सुविधा, 7वें साल के बाद आंशिक निकासी का विकल्प और मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाने का प्रावधान शामिल है। निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें कि महीने की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करने पर आप पूरे महीने का ब्याज पा सकते हैं।

एनसीएलएटी ने इटेल पर 27 करोड़ के जुर्माने पर लगाई रोक

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी इटेल कोरपोरेशन को बड़ी राहत देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए 27.38 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायाधिकरण की दो-सदस्यीय पीठ ने यह राहत इसलिए दी, क्योंकि इटेल पहले ही जुर्माने की 25 प्रतिशत राशि जमा कर चुकी है। इसके साथ ही सीसीआई को निर्देश दिया गया है कि वह आदेश के क्रियान्वयन के लिए कोई कठोर कदम न उठाए। इटेल ने सीसीआई के फरवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें भारत-विशिष्ट वारंटी नीति के माध्यम से प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का आरोप लगाते हुए जुर्माना लगाया गया था। सुनवाई के दौरान इटेल ने बताया कि उसने 1 अप्रैल, 2024 से अपनी भारत-विशिष्ट वारंटी नीति वापस ले ली है और इसे सार्वजनिक भी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की गई है।



वेदांता का कारोबार विभाजन एक मई से होगा प्रभावी

एल्यूमीनियम, बिजली, तेल-गैस और लौह अयस्क इकाइयां होंगी अलग सूचीबद्ध

नई दिल्ली ।

खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांता लिमिटेड ने अपने प्रमुख व्यवसायों के बहु-प्रतिष्ठित डीमर्जर (विभाजन) की प्रभावी तिथि की घोषणा कर दी है। कंपनी के निदेशक वेदांता ने हाल ही में हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि एल्यूमीनियम, बिजली, तेल एवं गैस और लौह अयस्क इकाइयों को अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में विभाजित करने की योजना 1 मई, 2026 से प्रभावी होगी। इस पुनर्गठन का उद्देश्य कंपनी की कॉरपोरेट संरचना को सरल बनाना और संचालन पर ध्यान केंद्रित करना है। इस डीमर्जर योजना के तहत, वेदांता चार अलग-अलग कंपनियों - वेदांता एल्यूमीनियम मेटल लिमिटेड (वीएएमएल), तलवंडी साबो पावर लिमिटेड, एनर्जी लिमिटेड और वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड को अलग से सूचीबद्ध करेगी। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड का नाम बदलकर वेदांता पावर और माल्को एनर्जी लिमिटेड का नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस किया जाएगा। वेदांता एल्यूमीनियम मेटल लिमिटेड को भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाकनो) में अपनी



शेयरधारिता भी हस्तांतरित करेगी। कंपनी ने बताया कि डीमर्जर के बाद, वेदांता के मौजूदा शेयरधारकों को प्रत्येक नई सूचीबद्ध कंपनी में 1:1 अनुपात में इक्विटी शेयर प्राप्त होंगे। पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए 1 मई, 2026 को रिपोर्ट तिथि निर्धारित की गई है। वेदांता के अनुसार, यह कदम क्षेत्र-केंद्रित स्वतंत्र कंपनियों का निर्माण करेगा, जिससे संप्रभु संपत्ति कोष, खुदरा और रणनीतिक निवेशकों सहित वैश्विक निवेशकों को वेदांता की विश्व स्तरीय संपत्तियों में प्रत्यक्ष निवेश के अवसर मिलेंगे। इससे विभिन्न व्यवसायों के सुगम संचालन में भी मदद मिलेगी। हालांकि, यह डीमर्जर प्रक्रिया कई बार स्थगित हो चुकी है। पहले 31 मार्च, 2025, फिर 30 सितंबर, 2025 और बाद में 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तय की गई थी। अब इसे 30 जून तक बढ़ाया गया है, क्योंकि कुछ सरकारी प्राधिकरणों से मंजूरी अभी भी लंबित है।

सलमान और नयनतारा की अगली फिल्म की शूटिंग शुरू

अनिल कपूर समेत कई सेलेब्स ने जाहिर की खुशी

सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' के बाद साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के साथ अगली फिल्म करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग से जुड़ा अपडेट मेकर्स ने साझा किया है। सलमान की इस फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर्स एक्साइटेटेड दिख रहे हैं। निर्देशक वामशी ने इंस्टाग्राम पर सलमान खान की आगामी फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की है। निर्देशक ने एक क्लैपरबोर्ड की तस्वीर अपलोड की, जिस पर 'मुहूर्त' लिखा हुआ था। इस तरह वामशी ने फैंस को बताया कि सलमान खान और नयनतारा की एक्शन ड्रामा फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। शनिवार को इसका मुहूर्त शॉट किया गया।

कई सेलेब्स ने शूटिंग को लेकर जाहिर की खुशी

डायरेक्टर वामशी की पोस्ट और सलमान खान की फिल्म को लेकर कई बॉलीवुड सेलेब्स उत्साहित दिखे। इस पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए अनिल कपूर ने लिखा, 'वामशी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।' इसी तरह नम्रता शिरोडकर ने भी कमेंट किया, 'बहुत-बहुत बधाई।' सलमान के फैंस ने भी इस पोस्ट को खूब लाइक किया है।



सलमान ने ही थी फिल्म की घोषणा

कुछ दिन पहले सलमान खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी इस फिल्म की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि वो अपनी अगली फिल्म तेलुगु निर्देशक और निर्माता के साथ करेंगे। सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर निर्देशक वामशी पंडिपल्ली के साथ एक तस्वीर भी शेयर की थी। इस तस्वीर के साथ सलमान ने लिखा, 'दिल, दिमाग और जिगर से इस अप्रैल से वामशी और दिल राजू के साथ।' शनिवार को इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो गई।

पार्वती कृष्णा योगा के नाम पर हो रहीं ट्रोल्

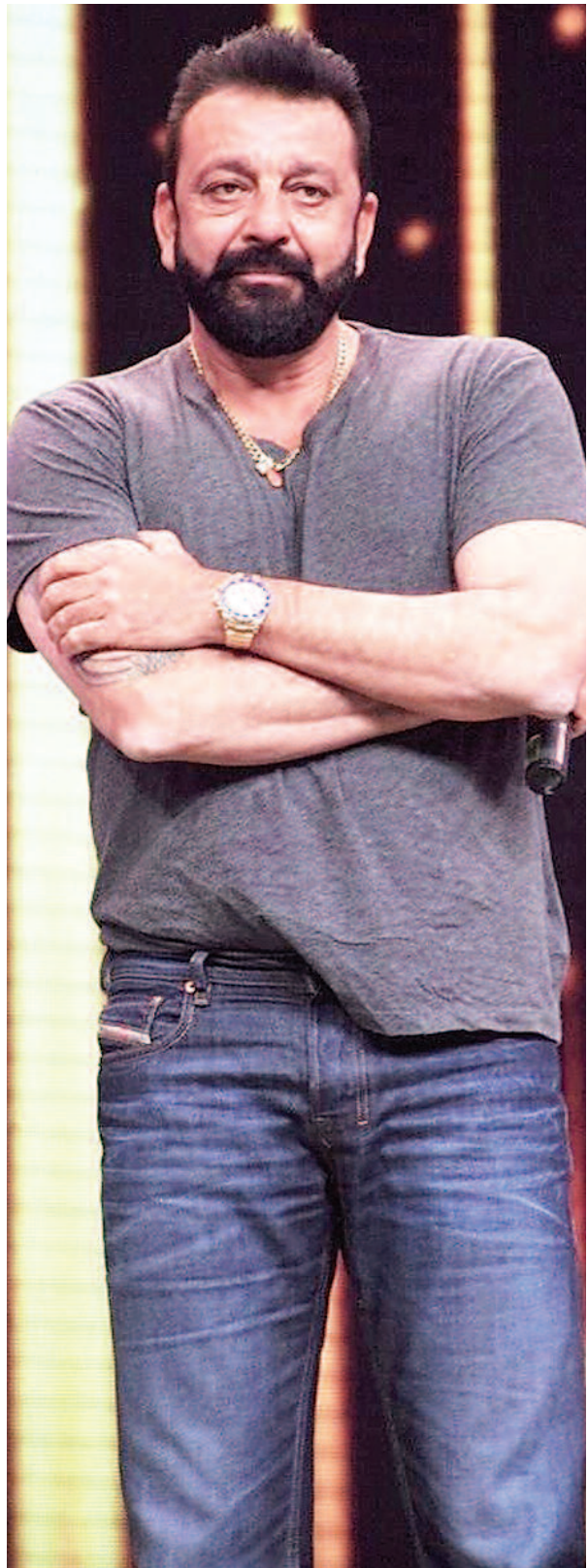
सोशल मीडिया पर पार्वती कृष्णा को कई लोग फॉलो करते हैं, वह बतौर एक्सपर्ट फेंस योगा सिखाती हैं। इसी वजह से वह एक विवाद का हिस्सा बन गईं और नेटिजंस द्वारा ट्रोल् भी की जा रही हैं। जानिए, क्या है ये पूरा मामला? और पार्वती कृष्णा का फिल्मी दुनिया से क्या रिश्ता है? पार्वती कृष्णा सोशल मीडिया पर दावा करती हैं कि वह फेंस योगा से शॉर्प जॉलान बनाने में लोगों की मदद करती हैं। इससे चेहरा काफी हद तक बदल सकता है। लेकिन यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। नेटिजंस ने फेंस योगा से चेहरे में बदलाव की बात को नाकार और इसे गुमराह करने जैसा बताया। खासकर एक यूट्यूबर चंद्रशेखर रमेश ने पार्वती कृष्णा के दावों की आलोचना की।

पार्वती ने दिया ट्रोल्स को जवाब

जब पार्वती कृष्णा की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग ज्यादा होने लगी तो एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने जवाब दिया। इसमें उनका कहना है कि वह एक फेंस योगा की एक्सपर्ट हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी है। वह कई लोगों की इस मामले में मदद कर चुकी हैं। ट्रोल् करने वालों पर भी पार्वती ने निशाना साधा है, इसमें यूट्यूबर चंद्रशेखर रमेश भी शामिल हैं। पार्वती के इंस्टाग्राम वीडियो पर कुछ लोगों ने उन्हें सपोर्ट भी किया है।

फिल्मों से क्या है पार्वती कृष्णा का कनेक्शन

पार्वती कृष्णा एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हैं। वह मलयालम फिल्मों में अभिनय करती हैं। साल 2014 में 'एंजल' नामक की फिल्म से पार्वती ने अपना करियर शुरू किया। फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल भी किए। इसमें 'ईश्वरन साक्षीयायी' और 'राजी माजा' जैसे सीरियल शामिल हैं। पार्वती ने कई शो भी होस्ट किए। मलयालम का पॉपुलर शो 'किडिलम' को भी वह होस्ट कर चुकी हैं।



पांच साल में बनाया भारत में सबसे बड़ा रिकॉर्ड

संजय की चार फिल्मों ने ली 1000 करोड़ क्लब में एंट्री

बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। उनकी अलग-अलग चार फिल्मों ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री ली है। ऐसा कोई खान स्टार या साउथ का स्टार नहीं कर सका।

यह आम राय है कि बॉक्स ऑफिस पर खान स्टार और साउथ के बड़े अभिनेताओं का दबदबा रहता है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है। पिछले कुछ वर्षों में एक एक्टर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो लोगों को हैरान कर रहा है। उन्होंने अलग-अलग भाषाओं की फिल्मों की हैं। उनकी चार फिल्मों 1000 करोड़ क्लब में पहुंची हैं।

अभिनेता ने खान और साउथ के कलाकारों को छोड़ा पीछे

यह कोई और अभिनेता नहीं बल्कि बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता संजय दत्त हैं। उनकी चार अलग-अलग फिल्मों ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। इस रिकॉर्ड की खास बात यह है कि कई बड़े स्टार्स ऐसे रिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं। इस लिस्ट में आमिर खान, शाहरुख खान और प्रभास जैसे सितारे हैं। हालांकि संजय दत्त इन सब लोगों से आगे हैं। कई सितारों की एक या दो ही फिल्मों 1000 करोड़ क्लब तक पहुंची हैं। लेकिन संजय दत्त की एक नहीं चार फिल्मों 1000 करोड़ क्लब तक पहुंची हैं।

इन फिल्मों ने कमाए 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा

संजय दत्त ने 'केजीएफ चैप्टर 2' (2022) में अपने विलेन के किरदार से काफी चर्चा बटोरी। संजय दत्त की यह पहली फिल्म थी जिसने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री मारी थी। इसके बाद 'जवान' ने 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। इसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे। 'धुरंधर' (2025) में भी संजय दत्त नजर आए थे। इस फिल्म ने 1300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया। इसी तरह से 'धुरंधर 2' (2026) ने एक महीने में 1700 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कलेक्शन किया है।

संजय दत्त के नाम बड़ा रिकॉर्ड

इस तरह से संजय दत्त अकेले ऐसे अभिनेता हैं, जिनकी 4 फिल्मों ने 1000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया है। उनका ये रिकॉर्ड काफी खास माना जा रहा है।



अक्षय कुमार बोले- मेरा बेटा 4500 की नौकरी कर रहा

एक्टर अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'भूत बंगला' से फैंस को खूब हंसा रहे हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके बेटे को फिल्मों में आने में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो फेशन में अपना करियर बना रहा है।

अक्षय कुमार का बेटा आरव भाटिया

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार दो दशकों से अधिक समय से अपनी फिल्मों से लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। उनकी पत्नी दिवंगल खन्ना भी कुछ समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थीं। हालांकि, एक्टर ने हाल ही में खुलासा किया कि उनके बेटे आरव को फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह फेशन में अपना करियर बना रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद कमा भी रहे हैं। अक्षय कुमार ने कहा कि उनका बेटा उनसे बहुत अलग नहीं है और आगे कहा, 'हम दोनों में बहुत समानता है। उसे फिटनेस का शौक है, और मुझे भी। वह लंबा है और बहुत ही फोकस्ड है। उसे काम करना पसंद है। लेकिन वह फिल्मों में नहीं आना चाहता। उसकी ऐसी कोई योजना नहीं है। वह फेशन में अपना करियर बनाना चाहता है।' वह बेचारा आज भी 4500 रुपये की नौकरी कर रहा है। अच्छी बात है, क्यों नहीं? वह गांवों में जाकर वहां से फेशन सीख रहा है, अलग-अलग तरह के प्रिंट्स वगैरह। मैं उसे ज्यादा उपदेश नहीं देता, लेकिन मैंने उसे हिदायत दी है कि किसी को नुकसान न पहुंचाए।

आरव भाटिया कौन है?

आरव भाटिया का जन्म 2002 में हुआ था और वे अक्षय कुमार और दिवंगल खन्ना के सबसे बड़े बेटे हैं। 15 साल की उम्र में वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए और फिलहाल लंदन के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी छोटी बहन नितारा (जन्म 2012) अक्सर दिवंगल के सोशल मीडिया पर नजर आती हैं, जबकि आरव लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं।

सनी देओल-आमिर खान की फिल्म 'लाहौर 1947' का बदला जाएगा टाइटल

सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'लाहौर 1947' लंबे वक्त से चर्चा में है, कुछ समय पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि इस फिल्म का नाम बदल सकता है, लेकिन ये महज अफवाह निकली। लेकिन अब एक बार फिर 'लाहौर 1947' का नाम बदले जाने की खबर सामने आई है।

सनी देओल ने 2026 की शुरुआत में 'बॉर्डर 2' बवाल काट दिया था। इसके बाद सनी देओल के पास कई बड़े फिल्ममेकर्स से ऑफर मिल रहे हैं। एक्टर के पास बहुत सी फिल्मों लाइनअप में शामिल हैं। सनी देओल इस साल 'गबरू', 'लाहौर 1947' और 'रामायण' से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले हैं। हाल ही में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स सामने आईं, जिनमें दावा किया गया कि सनी देओल की 'लाहौर 1947' का नाम बदला जाएगा। लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं थी। इसी बीच अब खबर मिली है कि वाकई में सनी देओल की फिल्म का नाम बदलने की पूरी तैयारी है।

'बॉर्डर 2' के बाद सनी देओल की 'लाहौर 1947' की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके बाद से ही फैंस में इसे लेकर जबरदस्त क्रेज है। ये फिल्म 13 अगस्त को थिएटरों में रिलीज होने वाली है। सनी देओल की इस फिल्म को आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं और राजकुमार संतोषी डायरेक्ट कर रहे हैं। बीते दिनों खुद आमिर खान ने बताया था कि 'लाहौर 1947' का नाम नहीं बदला जा रहा है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि 'लाहौर 1947' का नाम बदला जा रहा है और इसका नया टाइटल भी पता चल गया है।

लाहौर 1947 का बदलेगा नाम?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 की मच अवेटेड फिल्म 'लाहौर 1947' का नाम बदलने के बारे में सोचा जा रहा है। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी सनी देओल और आमिर खान की फिल्म 'लाहौर 1947' का नाम बदलकर अब 'बंदवारा 1947' किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक मेकर्स ने कोई ऐलान नहीं किया है लेकिन ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही मेकर्स 'बंदवारा 1947' पर मुहर लगा सकते हैं।



सोनाली ने बिग बॉस मराठी पर लगाए गंभीर आरोप



अभिनेत्री सोनाली राउत ने बिग बॉस मराठी सीजन 6 के निर्माताओं पर शो के दौरान अस्वच्छ (अनहाइजीनिक) रहने की स्थिति का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि खराब वातावरण के कारण उन्हें खुजली की बीमारी हो गई। उन्होंने किचन से लेकर वॉशरूम तक में गंदगी होने और मुरे हुए चूहे और कॉकरोच मौजूद होने के आरोप लगाए थे। सोशल मीडिया पर सोनाली ने अपने शरीर पर, पीठ, बांहों, पैरों और धड़ सहित, चकत्ते और निशान दिखाते हुए वीडियो साझा किए।

एक ही वॉशरूम इस्तेमाल करते थे 17 कंटेस्टेंट

सोनाली राउत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने स्थितियों को दयनीय बताया, जिसमें रसोई में चूहे किराने का सामान कुतर रहे थे और खाने में कॉकरोच पाए जा रहे थे। साथ ही पोस्ट में सोनाली ने अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें उन्होंने अपने शरीर पर निकले दाने, निशान और चकत्ते दिखाए।

मणिपुर में कापी धरती, 5.2 तीव्रता का आया भूकंप, सो रहे लोग घरों से आए बाहर

-जापान में भूकंप के बाद कुजी बंदरगाह पर 80 सेंटीमीटर ऊंची दिखी सुनामी लहरें



इम्फाल (एजेंसी)। मंगलवार तड़के मणिपुर में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। वहीं दूसरी ओर जापान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद समुद्र की लहरों ने तटीय इलाकों में दस्तक दी है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केन्द्र के मुताबिक मंगलवार सुबह 5-59 बजे मणिपुर के कामजोग जिले में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 62 किलोमीटर नीचे था। सुबह के समय आए इन झटकों से लोग डरकर घरों से बाहर आ गए। फिलहाल राज्य के किसी भी हिस्से से नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं दूसरी ओर जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि इवारी प्रांत के कुजी बंदरगाह पर 80 सेंटीमीटर ऊंची सुनामी देखी गई। शाम 4-53 बजे आए भूकंप की तीव्रता जापान के भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर 7 में से 5 के ऊपरी स्तर पर दर्ज की गई और इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने पिछले एक सप्ताह से इसी तरह के भूकंपों की चेतावनी जारी की थी। जापानी मौसम एजेंसी ने होकाइडो, आओमोरी और इवारी प्रांतों के प्रशांत तटों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है और तत्काल 3 मीटर तक ऊंची लहरों के आने का पूर्वानुमान लगाया है। जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से ऊंची जगहों पर जाने का आग्रह किया।

'आई-पैक' ने 1300 कर्मियों को छुट्टी पर भेजा, तरह-तरह के उठ रहे सवाल

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में तुणमूल कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी का चुनावी कैम्पेन संभाल रही फर्म 'आई-पैक' का कोलकाता के विधानसभा स्थित दफ्तर दो दिनों से बंद है। सूत्रों के मुताबिक इसके प्रचार ने 1300 कर्मियों को छुट्टी पर भेज दिया है। यह सच ऐसे समय हुआ है जब पहले चरण का मतदान को कुछ दिन ही बचे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान होगा है। चुनाव प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया। दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को है। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तुणमूल की बृथ लेवल की गतिविधि से लेकर नेताओं की सभाएं, रैलियां, सब कुछ तय करने में आईपैक एक पॉलिटेक्निक कंसल्टेंसी कंपनी की अहम भूमिका निभा रही है। बंगाल में पार्टी के मौजूदा कर्तबगार 33 फीसदी विधायकों के टिकट काटने के फैसले के पीछे भी इसी का बड़ा आधार था। इसने बंगाल के 93 हजार पोलिंग बूथों के लिए एक लाख बूथों एजेंट्स तैयार किए थे। टीएमसी भले ही इसके बंद होने की खबरों को खारिज कर रही है, लेकिन मतदान से ठीक पहले संपादन और कार्यकारी असमंजस में आ गए हैं। हालांकि पार्टी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इस संसद में दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी है। 15 एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं। सभी ठीक हैं। पार्टी के एक अन्य नेता ने बताया कि टीएमसी संगठन 4 स्तर पर काम कर रहा है। इस बीच, टीएमसी ने आश्चर्यजनक है कि उसके 800 नेताओं, कार्यकर्ताओं को केंद्रीय सुरक्षा बल एहतियातन गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुके सुनाई की मांग की है। पार्टी को आशंका है कि केंद्रीय बल राज्य के पुलिस थानों को कब्जे में ले सकते हैं।

दिल्ली में शराब के बाद गुजरात में हवाला कांड में फंस सकती आम आदमी पार्टी

श्रीनगर (एजेंसी)। सूरत (ईएमएस)। गुजरात के सूरत जिले में सामने आए कथित हवाला मामले ने आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिदले के कथित शराब घोटाले में ट्रायल कोर्ट से राहत मिलने के बाद जहां मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, वहीं अब गुजरात से एक नया विवाद सामने आया गया है। सूरत पुलिस ने दावा किया है कि एक बड़े हवाला रेकेट का खुलासा किया है, जिसमें पार्टी के कुछ पदाधिकारी शामिल हैं और जांच की आंच बड़े नेताओं तक भी पहुंच सकती है। पुलिस ने हवाला मामले में आकाश मिश्रा और अजय तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये दोनों हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे के लेनदेन में शामिल थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह नेटवर्क कथित तौर पर दिल्ली से संचालित हो रहा था और इसमें पार्टी के विरिष्ठ नेताओं के निदेश होने की भी आशंका जाहिर की गई है। सूरत पुलिस की जांच में देखा जा रहा है कि क्या इन पैसों का उपयोग गुजरात की पबल सरकार के खिलाफ माहौल बनाने और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने के लिए किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिश्रा पहले सरचिट्तौन के साथ काम कर चुका है और कई रायों—दिल्ली, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा है। आरोप है कि हवाला के जरिए मिले पैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को देते थे, ताकि वे गुजरात सरकार के विरोध में माहौल तैयार करें और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दें। इस मामले में आ्यकर सिंघानि की जांच शुरू की है। जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपियों ने सूरत के महिधपुरा इलाके में एक अंगणिका से कई बार 15-20 लाख तक की रकम प्राप्त की।

कोलकाता के आनंदलोक अस्पताल में भीषण आग... 75 से 80 मरीजों को बाहर निकाला गया

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता के मशहूर आनंदलोक अस्पताल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने अस्पताल की कई मंजिलों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है और इसकी जांच जारी है। आग लगने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। स्ट्रुचर और हीलथेयर की भदद से करीब 75 से 80 मरीजों को बाहर निकालकर पास की इमारतों में पहुंचाया गया।

देश में गर्मी ने पकड़ा जोर, कई जगह पारा 45 डिग्री पर पहुंचा, विदर्भ में लू की मार

-उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अलग-अलग इलाकों में हीटवेव की संभावना

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के कई हिस्सों में गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। यूपी के बांदा में 17 अप्रैल को 45 डिग्री तापमान दर्ज करने वाला पहला शहर बना गया। विदर्भ के वर्धा में भी तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, विदर्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। नागपुर, गोंदिया, अमरावती समेत कई इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है। पूरा विदर्भ क्षेत्र लू की मार झेल रहा है। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, सुल्तानपुर और फुर्सतगंज में लू का असर देखा जा सकता है। आने वाले दिनों में भी विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में तापमान ज्यादा रह सकता है।



नहीं बढ़ेगा। इस हफ्ते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनने के आसार जताए जा रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक इस साल अप्रैल के तापमान में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। बीते सालों में जहां अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी का भयानक कहर शुरू हो जाता था, इस बार गर्मी का असर देर से महसूस हुआ है। साल 2026 में अप्रैल महीने में 16 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि 17 अप्रैल को यह बढ़कर 41.0 डिग्री पहुंच गया था। वहीं, साल 2025 में अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान 40 डिग्री के पार चला गया था।

नई दिल्ली (सफ़्दरजंग) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में अप्रैल महीने का सबसे ज्यादा तापमान 43.5 डिग्री रहा, जो 29 और 30 अप्रैल 2022 को दर्ज किया गया था। वहीं, नई दिल्ली (पालम) में पिछले पांच सालों में अप्रैल का सबसे ज्यादा तापमान 44.0 डिग्री दर्ज किया गया, जो 30 अप्रैल 2022 को रिकॉर्ड हुआ था। बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में हीटवेव की स्थिति बनी रह सकती है। ज्यादा पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा आने वाले दिनों में उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अलग-अलग इलाकों में हीटवेव की संभावना है। पंजाब, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के कुछ इलाकों में 24 अप्रैल तक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 अप्रैल तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 23 अप्रैल के आसपास एक नया मिस्ट्रम पश्चिमी हिमालय तक पहुंचेगा, हालांकि इसका असर मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित रहने की संभावना है। दिल्ली में कुछ दिनों तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीटवेव जैसी स्थिति बनने की प्रबल संभावना है, और कुछ स्थानों पर तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है।

हाईकोर्ट ने मोहन भागवत की जेड प्लस सुरक्षा पर खर्च को लेकर याचिका खारिज की

-याचिकाकर्ता की मंशा पर जताई शंका, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप नहीं माने

नागपुर (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिली जेड प्लस सुरक्षा पर होने वाले खर्च को लेकर दायर जनाहित याचिका को बांबे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। अदालत ने न केवल याचिका को अस्वीकार किया, बल्कि याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल उठाए।



यह मामला हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष आया था, जहां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति जस्टिस अनिल किलोर की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में दावा किया गया था कि भागवत को दी गई जेड प्लस सुरक्षा पर हर महीने लगभग 40 से 45 लाख रुपये खर्च हो रहे हैं, जो करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है। नागपुर निवासी ललन सिंह द्रौढ़ दायर इस याचिका में कहा गया था कि जूट आरएसएस एक पंजीकृत संपादन नहीं है, इसलिए उसके प्रमुख को दी जा रही सुरक्षा का खर्च सरकार की बजय

संगठन को वहन करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस खर्च की भरपाई संघ से कराई जाए। याचिका में मुकेश अंबानी से जुड़े एक मामले का भी हवाला दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में निर्देश दिया था कि उन्हें दी गई जेड प्लस सुरक्षा का खर्च उनके परिवार द्वारा उठाना जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता के इरादों पर सवाल उठाए। अदालत ने संकेत दिया कि इस तरह की याचिकाएं जनहित के नाम पर दाखिल की जाती हैं, लेकिन उनके पीछे वास्तविक उद्देश्य संदिग्ध हो सकता है। गौरतलब है कि मोहन भागवत की सुरक्षा को जून 2015 में बढ़ाकर जेड प्लस श्रेणी में किया गया था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआइएसएस को सौंप दी गई थी। इससे पहले उनकी सुरक्षा महाराष्ट्र पुलिस के पास थी। उल्लेखनीय है कि उन्हें पहली बार 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी, जब सुशील कुमार शिंदे देश के गृहमंत्री थे।

तमिलनाडु चुनाव: स्टालिन की होगी वापसी, बीजेपी खाता खुलना भी मुश्किल!

-डीएमके गठबंधन को 120 से 140 तो एआईएडीएमके को मिल सकती है 90 सीटें

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु की 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा है। सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत होगी। मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच है। एक तरफ सीएम एमके स्टालिन का द्रविड़ियन मोड़ल और उनकी पॉपुलर योजनाएं हैं, दूसरी तरफ जयललिता की विरासत संभाल रही एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन है।



मोडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में स्टालिन सरकार की वापसी हो सकती है। डीएमके को 120 से 140 सीटें मिल सकती हैं। इनमें डीएमके को 100 से 110, कांग्रेस को 10 से 15 और गठबंधन की बाकी पार्टियों को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। 2021 में डीएमके को 133 और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थीं। गठबंधन ने 159 सीटें जीती थीं। डीएमके ने

कारैकुडी सीट पर जीत के ज्यादा चांस हैं। गठबंधन की बाकी पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। 2021 में एआईएडीएमके ने 66 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती थीं। गठबंधन को सिर्फ 75 सीटें मिली थीं। रिपोर्ट के मुताबिक तमिल फिक्न्सों से सुपरस्टार थलापति विजय की नई पार्टी का वोट शेयर 12 फीसदी रह सकता है। टीवीके पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार एक्टर सीमान की पार्टी नाम तमिल कान्ची (एनटीके) और कमल हासन की मक्कल नीधि मयम (एमएनएम) का खाता नहीं खुला था। रहा है, लेकिन पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो 5 सीटें मिल सकती हैं। कोयंबटूर साइथ, तिरुनेलवेली, नागकोइल, मोडकुरिची और

जाती हैं। स्थानीय और जातीय वाली पार्टियों को साथ लाए। कलेगनार मालिगर उरीमाई थोगाई सकती है। 2021 में एआईएडीएमके को एक हजार रुपए महीने दिया। ये पैसा करीब एक करोड़ महिलाओं को मिला। सरकार बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर बढ़ा फैक्टर है। सरकारी स्कूल से पढकर कॉलेज में जाने वाली लड़कियों को हर महीने एक हजार रुपए दिए गए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए। इन्फका फायदा लेने वाली युवा फर्स्ट टाइम वोटर हैं। तमिलनाडु में करीब 12.5 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक गठबंधन की कमजोरी कांग्रेस है। उसे 28 सीटें मिली हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक राज्य में कम ही सक्रिय रहे। कांग्रेस ने प्रचार का पूरा जिम्मा डीएमके को सौंप दिया है।

केदारनाथ मंदिर कमेटी का फैसला...न मोबाइल, न फोटो, और न ही वीडियो या इंस्टाग्राम रील बनाएं

देहरादून। केदारनाथ मंदिर की पवित्रता और धार्मिक मर्यादा बनाए रखने के लिए मंदिर समिति ने बड़ा निर्णय लिया है। अब मंदिर परिसर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। समिति के सदस्य विनीता पोस्टी के अनुसार, श्रद्धालु मंदिर के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते और न ही फोटो, वीडियो या इंस्टाग्राम रील बना पाएंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें सजा का प्रावधान भी शामिल हो सकता है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण में दर्शन का अनुभव कराना है। देहरादून से मिली जानकारी के अनुसार, मंदिर समिति ने सभी यात्रियों से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है ताकि धार्मिक स्थल की गरिमा बनी रहे। वहीं, रुद्रप्रयाग पुलिस प्रशासन ने आगामी केदारनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए व्यापक यातायात प्रबंधन योजना तैयार की है। इस योजना के तहत यात्रा मार्गों पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने, भीड़भाड़ कम करने और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों से लेकर संपर्क मार्गों तक यातायात व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और स्थायी व अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि जाम की स्थिति से बचा जा सके। पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि जिले को 2 सुपर जॉन और 11 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही 13 मोबाइल पुलिस टीमें भी तैनात रहेंगी। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाएगा। यह पूरी योजना श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।

अपर्णा और शाही के सपा-कांग्रेस का झंडा जलाने पर बीजेपी नाराज, पार्टी की हुई किरकिरी

-अखिलेश ने कहा था- बीजेपी वाले 12 करोड़ आबादी वाले यूपी में सिर्फ 12 महिलाएं भेजे



लखनऊ (एजेंसी)। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर बिल के पारित ना होने पर यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और सदस्य ऋतु शाही ने सपा-कांग्रेस का झंडा जलाकर विरोध जताया था। अब दोनों महिला नेताओं के इस प्रदर्शन पर बीजेपी नेतृत्व नाराज है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव और सदस्य ऋतु शाही पर पार्टी हाईकमान ने सवाल उठाए हैं कि इसमें पार्टी की किरकिरी हुई है।

बता दें 17 अप्रैल की देर रात विधानसभा के बाहर अपर्णा यादव और ऋतु शाही ने महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने सपा और कांग्रेस के झंडे जलाए और विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के गिर जाने के विरोध में किया गया था। अपर्णा ने कहा था कि यह कलंकित करने वाली राह है। विपक्ष का

आला कमान दोनों ही नेताओं से नाराज है। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह सहित कई बड़े नेता इस घटना से नाराज हैं। उनका कहना है कि बिना पार्टी की अनुमति के और इतनी कम संख्या में प्रदर्शन करना पूरी पार्टी को बदनाम करने जैसा था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अपर्णा यादव और ऋतु शाही से या तो लिखित स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है या फिर मौखिक जुवाब।

बता दें सुलभम सिंह यादव की छोटी बहन अपर्णा यादव 2022 में सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थीं। ऋतु शाही एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेश कुमार शाही की पत्नी हैं और पहले बीजेपी की गोरखपुर इकाई की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। बताया जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण से बीजेपी की रणनीति को धक्का लगा है, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष के विरोध के बाद इसे बड़ा मुद्दा बनाने के फिर्का में है। फिलहाल दोनों महिला नेताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

तुम से न हो पाएगा... कहकर तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर कस दिया तंज

इंडिया गठबंधन को प्रियंका गांधी वाड़ा ही चला सकती

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से इंडिया गठबंधन नहीं चल पाएगा है। लालू के बड़े बेटे ने कहा कि प्रियंका गांधी वाड़ा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकती हैं और उनमें यह क्षमता है। तेज प्रताप ने कहा, प्रियंका गांधी वाड़ा ही चला सकती हैं। वे इंडिया गांधी जी की तरह हैं। राहुल गांधी से गठबंधन चलने वाला नहीं है। यात्रा निकालने से या फिर बुटेट पर बैठ जाने से गठबंधन नहीं चलता। इस तरह तेज प्रताप ने कांग्रेस के सर्वोच्च राहुल गांधी पर ही सीधा सवाल उठा दिया है।



नीतीश कुमार के बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि वह कांग्रेस में इस्तीफा दे दें। इस

दूसरे नेता आए और सीएम बन गए। राहुल गांधी को बिहार को लेकर लालच क्यों लगा रहा है। उन्हें क्या यहां पर मुख्यमंत्री का पद चाहिए।

बात दें कि तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी से बनावत की थी। वह अपने जनसत्ता दल की ओर से ही खुद लड़ें थे और कैबिनेट भी उतारे थे। हालांकि तेज प्रताप यादव खुद हार गए थे और उनके उतारे किसी कैबिनेट को भी जीत नहीं मिली थी। तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव में सीधे हमले करते नहीं दिखे थे, लेकिन उनके करीबियों पर खुब बचाव चलाए थे। इतना ही नहीं उनकी बहन रेहिंगी आचार्य गांधी भी चला सकती हैं। राहुल गांधी जो से चलने वाला नहीं है। तेज प्रताप ने कहा कि अब नीतीश के मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर बात कर रहे हैं। नीतीश छोड़कर गए, तब

भारत और रूस एक-दूसरे के देशों में हजारों सैनिक, फाइटर जेट और वॉरशिप तैनात करने की तैयारी में

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-ईरान जंग के बीच एक बड़ी हलचल हुई है। जिसका ध्यान पूरी दुनिया से खींचा है। दरअसल भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर अपने हजारों सैनिक, फाइटर जेट और वॉरशिप तैनात करने की तैयारी शुरू कर रहे हैं। बता दें कि भारत और रूस के बीच रीलोंस यानी कि रैस्पोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता पूरी तरह से लागू हो गया है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के एयरबेस, नेवल बेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वह भी पूरी सफाई के साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। इस डील की सबसे बड़ी ताकत इसकी क्षमता है। अब दोनों देश एक साथ 3000

सैनिक, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और पांच वॉरशिप एक दूसरे के क्षेत्र में तैनात कर सकते हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ तैनाती नहीं है बल्कि उस तैनाती को मिलने वाला रूप सपोर्ट है। यानी कि रिफ्लिंग, रिपैर, मटेनेंस, मेडिकल और ट्रंसपोर्ट यानी पूरी युद्ध मशीन को कहीं भी चलाने की ताकत। अब भारत की सेना सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तेजी से ऑपरेट कर सकती है। बात दें कि आज दुनिया एक नए पारगम में है। जहां हर देश अपने सप्लाइ स्ट्रस और मिलिट्री रीच को सुरक्षित करने में लगा है। दूसरी जगह दुनिया भर में चीन का बढ़ता असर है। चीन लगातार

एशिया और इंडोपैसिफिक में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके बाद भारत के लिए अपनी मौजूदगी बढ़ाना जरूरी था। तीसरी वजह रूस की रणनीति को मना जा रहा है। पश्चिमी दबाव के बीच रूस को इसतरह के पॉन्टर की जरूरत थी जिस पर भरोसा कर सके और भारत रूस के लिए दुनिया में सबसे भरोसेमंद दोस्त है। इस बीच भारत ने जो रास्ता चुना है वह सबसे अलग है। न पुरी तरह किसी एक के साथ और न किसी के खिलाफ बल्कि अपने हितों के हिसाब से हर बड़े देश के साथ संतुलन बनाकर चलना। रूस के पास आर्कटिक से लेकर यूरोप तक फैले सैन्य बेस हैं और इस डील के बाद भारत को इन इलाकों में एक्ससेस मिल सकता

है। खासकर आर्कटिक जहां भविष्य के नए समुद्री रास्ते बन रहे हैं। यानी आने वाले समय में व्यापार और संसाधनों पर सीधा असर होगा। दूसरा लॉजिस्टिक मतलब रियल पावर मिलना है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि सप्लाइ से भी जीता जाता है। अब भारत और रूस एक दूसरे को फुल, रिपैर बेस सपोर्ट दे सकते हैं। मतलब जहां जरूरत वहां ऑपरेशन आसान। तीसरा स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी जिसका पहले हमने जिक्र किया। यानी कि भारत ने अमेरिका के साथ एलई एमओए किया और अब रूस के साथ रिलोस। मतलब साफ है भारत किसी एक एट में नहीं बल्कि हर बड़ी ताकत के साथ संतुलन बनाकर चल रहा है।

